राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 338, पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार , 17 जून 2021 मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट पर सुनवाई आज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सीबीएसई, आईसीएसई समेत तमाम राज्यों के बोर्ड 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन किस तरह करेंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। इस संबंध में कोर्ट में पिटीशन दायर की गई, जिस पर शीर्ष कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछले दिनों तमाम केंद्रीय और राज्यों के बोर्ड ने कोरोना के खतरे को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके बाद से बोर्ड मूल्यांकन क्राइटेरिया पर मंथन कर रहे हैं। उम्मीद है कि सीबीएसई प्रबंधन गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को क्राइटेरिया बता सकता है। सीबीएसई ने 12वीं के छात्र-छात्राओं के मूल्यांकन का क्राइटेरिया तय करने के लिए 13 सदस्यों का एक पैनल गठित किया था।

दिल्ली एम्स में नौवीं मंजिल पर लगी आग

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली एम्स में देर रात करीब 11.30 बजे अचानक आग लग गई। आग की लपटें और धुआं काफी दूर से नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आग कन्वर्जन ब्लॉक की नौवीं मंजिल पर लगी । राहत की बात है कि इस मंजिल में लैब और बाकी ऑफिस हैं। यहां पर कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है, जहां पर मरीज एडमिट होता हो। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि रेस्क्यू के लिए दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी थीं। अब तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। खबर लिखे जाने तक दमकलकर्मी आग पर काबू के लिए प्रयासरत थे। सूत्रों के मुताबिक आग नौवीं मंजिल पर एक रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी।

थरूर पर अब दो जुलाई को तय होगा आरोप

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत यहां एक होटल में रहस्यमय परिस्थितियों मृत पाई गई सुनंदा पुष्कर मौत मामले में उनके पति एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के खिलाफ अब दो जुलाई को आरोप तय करेगी। राऊज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज गीतांजली गोयल ने बुधवार को श्री थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए दो जुलाई की तारीख मुकर्रर की। एकल पीठ ने पिछली सुनवाई में कहा था कि यदि इस संबंध में 16 अप्रैल तक कोई आदेश नहीं सुनाई जाता है तो कम अवधि का समय दिया जाएगा। आपराधिक मामले में श्री थरूर के खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें पूरी करने के बाद पीठ ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

बंगाल में टीएमसी में घर वापसी की लगी होड़

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के दिग्गज नेता मुकुल रॉय की वापसी के बाद से ही कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भाजपा से लोग टीएमसी में आएंगे। मुकुल लगातार भाजपा नेताओं और संगठन के संपर्क में हैं। साथ ही उन लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं, जिन्हें वे चार साल भाजपा में रहते हुए टीएमसी से लाए थे। 2017 में तृणमूल से भाजपा में जाने वाले मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल में वापस लौट आए थे। ममता ने उनकी वापसी पर कहा था कि मुकुल को पार्टी में बड़ा रोल दिया जाएगा। बेटे शुभ्रांशु ने मुकुल के प्लान को और विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कम से कम 20 से 25 विधायक और 2 सांसद तृणमूल में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद किया, अब उसका जवाब देने का वक्त है।

टेक्नोलॉजी और डिजिटल हैं सहयोग के नये उभरते हुये क्षेत्र : मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को विवाटेक सम्मेलन के पांचवें संस्करण को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत में स्टार्टअप के लिए अच्छा माहौल है, निवेशक यहां आएं और निवेश करें। उन्होंने यह भी कहा किआधार ने महामारी के दौरान लोगों को समय पर मदद पहुंचाने में मदद की, लोगों को मुफ्त राशन, खाना पकाने के लिए ईंधन दिया गया।

विवा टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड के दो टीके भारत में बनाए गए हैं, कुछ और टीको के विकास एवं परीक्षण का काम चल रहा है। उन्होंने कहा किमैं प्रतिभा, बाजार, पूंजी, परिवेश और खुलेपन की संस्कृति ए इन पांच स्तंभों के आधार पर दुनिया को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी के कारण उत्पन्न बाधा के बाद हमें स्वास्थ्य सुविधाओं और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त और तैयार करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप को स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षण-प्रशिक्षण के नए तौर तरीकों के क्षेत्र में संभावना तलाशनी होगी।

इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ओर विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री और सांसद भी इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ताओं में शामिल हैं।

पीएम ने किया था ट्वीट -प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने ट्वीट में कहा कि बुधवार को मैं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विवाटेक सम्मेलन को संबोधित करूंगा। इस मंच से मैं प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप्स की दुनिया में भारत की उन्नति के बारे में अपनी बात रखूंगा। इस कार्यक्रम में एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक, फेसबुक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रेड स्मिथ सहित कॉर्पोरेट जगत की अन्य जान-मानी हस्तियां भी शामिल होंगी।

विवाटेक यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है और 2016 से हर साल पेरिस में इसका आयोजन किया जाता रहा है। विज्ञापन और मार्केटिंग जगत की प्रमुख कंपनी पब्लिसीज ग्रुप और फ्रांस के अग्रणी मीडिया समूह लेस इकोज की ओर से संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। पीएमओ के मुताबिक, यह आयोजन प्रौद्योगिकी नवाचार और स्टार्टअप इको सिस्टम के हितधारकों को एक साथ लाता है। इस आयोजन में प्रदर्शनियां, पुरस्कार, पैनल चर्चा और स्टार्टअप प्रतियोगिताएं शामिल की जाती हैं। बता दें कि विवाटेक सम्मेलन के पांचवें संस्करण का आयोजन 16 से 19 जून के बीच हो रहा है।

शिवराज और पीएम मोदी के बीच बैठक

नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार होने की खबरें छन-छन कर बाहर आ रही हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिनों हुई बैठकों ने इसे ओर हवा दे दी है। राज्यों में कुर्सी को लेकर खींचतान की खबरें भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की कशमकश पर भाजपा ठंडा पानी डाल चुकी है। कुछ दिनों पहले ऐसी ही खबरें मध्यप्रदेश से भी आई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज बैठक हुई। हालांकि बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में कोविड की वर्तमान स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने कोरोना नियंत्रण को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी दी व तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों पर पीएम से चर्चा की।

सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार रात दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने रात में ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। वे आज दोपहर 3ः15 बजे केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा से मिलेंगे। इसके बाद शिवराज शाम 4 बजे रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे।

प्रियंका गांधी वाड्रा की अपील- सुप्रीम कोर्ट करवाए राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले की जांच

नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में इस मामले की जांच करानी चाहिए.

प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा, 2 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन सिर्फ पांच मिनट के बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाए गए श्रीराम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से 18.5 करोड़ रुपये में खरीद ली गई. यानी जमीन की कीमत 5.5 लाख रुपये प्रति सेकंड की दर से बढ़ गई. यह सारा पैसा हिंदुस्तान की जनता द्वारा मंदिर निर्माण के लिए दान के रूप में दिया गया था.

कांग्रेस महासचिव ने दावा किया, जमीन की खरीदी-बिक्री से सम्बंधित बैनामे और रजिस्ट्री में गवाहों के नाम समान हैं. एक गवाह मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो आरएसएस के पूर्व प्रांतीय कार्यवाहक रहे हैं और दूसरे गवाह भाजपा नेता और अयोध्या के महापौर हैं. कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के मुताबिक, खबरों में कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी की ओर से भी ट्रस्ट के संचालन में मनमानी और अपारदर्शिता का आरोप लगाया गया है. उन्होंने यह भी कहा, श्रीराम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री जी ने किया था. प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी लोग इसमें ट्रस्टी हैं. ट्रस्ट का सीधा आशय भरोसे से होता है. प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि प्रभु श्रीराम के नाम, भक्तों द्वारा चढ़ाई गई पाई-पाई का इस्तेमाल आस्था से जुड़े सामूहिक कार्य में हो, न कि किसी घोटाले में.

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि आस्था में अवसर तलाशने का कोई भी प्रयास करोड़ों भारतीयों की आस्था पर चोट है और महापाप है. उन्होंने आग्रह किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर श्रीराम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ है. देशवासियों की तरफ से हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अपनी निगरानी में जांच करवाए.

चिराग पासवान बोले- हनुमान को अगर राम से मदद मांगनी पड़े, तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के !

नई दिल्ली । लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के नेता चिराग पासवान ने जेडीयू को अपनी पार्टी में विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले गुट द्वारा लिए गए फैसलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया पार्टी का संविधान उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं देता है. पार्टी में विभाजन के बाद मीडिया के साथ अपनी पहली बातचीत में, उन्होंने खुद को शेर का बेटा बताया और कहा कि वह अपने पिता रामविलास पासवान द्वारा स्थापित पार्टी के लिए लड़ेंगे.

विभाजन के लिए जेडीयू को दोषी ठहराते हुए, उन्होंने इस घटनाक्रम में बीजेपी की भूमिका के बारे में सवालों से किनारा कर लिया और कहा कि जो हुआ है वह एक आंतरिक मामला है, जिसके लिए वह दूसरों को निशाना नहीं बनाएंगे. उन्होंने कहा कि हनुमान को अगर राम से मदद मांगनी पड़े तो फिर वह हनुमान काहे के और वह राम काहे के. मालूम हो कि बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान चिराग पासवान ने खुद को हनुमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम कहा था.

चाचा से बात करने की कोशिश की- चिराग पासवान- एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि यह सब तब हुआ जब मैं बीमार था. मैंने उस समय अपने चाचा से बात करने की भी कोशिश की लेकिन मैं असफल रहा. उन्होंने कहा कि सदन के नेता की नियुक्ति पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है, न कि मौजूदा सांसद. ऐसी खबरें आई हैं कि मुझे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है. पार्टी के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष को केवल तभी हटाया जा सकता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा देता है. चिराग ने कहा कि अगर मेरे चाचा मुझे बोलते कि वो संसदीय दल के नेता बनना चाहते हैं तो मैं तैयार हो जाता. बिहार चुनाव के दौरान, उससे पहले भी, उसके बाद भी कुछ लोगों द्वारा और खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) द्वारा हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर किया जा रहा था. मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैने चुनाव लड़ा. कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे. मेरे चाचा ने खुद चुनाव प्रचार में कोई भूमिका नहीं निभाई. मेरी पार्टी के कई और सांसद अपने व्यक्तिगत चुनाव में व्यस्त थे.

राम मंदिर पर टिप्पणी को लेकर मुंबई में शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं आमने-सामने आए

मुंबई । सामना के संपादकीय में राम मंदिर को लेकर बीजेपी की खिंचाई की गई है जिसके बाद बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ता दादर में शिवसेना के मुख्यालय की ओर प्रदर्शन के लिए जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया. इस दौरान बीजेपी यूथ विंक के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के खिलफ जमकर नारेबाजी की.

पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गाड़ी में भरकर मौके से लेकर दूर चली गई. इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्तोओं ने राम मंदिर के समर्थन में और जय श्री राम का नारा लगाते रहे.

बीजेप के कार्यकर्ताओं के शिवसेना भवन पहुंचने से पहले ही वहां पर दादर माहिम विधानसभा के विधायक सदा सर्वांकर अपने समर्थकों के साथ खड़े थे. सदा सर्वांकर शिवसेना के विधायक हैं. जैसे ही बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आमने-सामने हुए तो दोनों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई. उन्होंने कहा कोई भी हमारे शिवसेना भवन की तरफ देखेगा तो उसके साथ यही हाल होगा. विधायक इस मारपीट को जायज ठहरा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से जवाब दिया है. विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ता मौके पर ही बैठ गए और नारेबाजी करने लगे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र मिशन को मंजूरी प्रदान की, जावड़ेकर ने गिनाए फायदे

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'गहरे समुद्र मिशन' को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी. इस मंजूरी के बाद समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता की हुई आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गहरे समुद्र के तले एक अलग ही दुनिया है. पृथ्वी का 70 प्रतिशत हिस्सा समुद्र है. उसके बारे में अभी बहुत अध्ययन नहीं हुआ है.

उन्होंने बताया कि सीसीईए ने ''गहरे समुद्र संबंधी मिशन'' को मंजूरी प्रदान कर दी है. इससे एक तरफ ब्लू इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी साथ ही समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी.

जावड़ेकर ने बताया कि समुद्र में 6000 मीटर नीचे कई प्रकार के खनिज हैं. इन खनिजों के बारे में अध्ययन नहीं हुआ है. इस मिशन के तहत खनिजों के बारे में अध्ययन एवं सर्वेक्षण का काम किया जायेगा. उन्होंने बताया कि इसके तहत समुद्रीय जीव विज्ञान के बारे में जानकारी जुटाने के लिये उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना की जायेगी. इसके अलावा थर्मल एनर्जी का अध्ययन किया जायेगा. जावड़ेकर ने बताया कि इस बारे में अभी दुनिया के पांच देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन के पास ही प्रौद्योगिकी.

चोकसी की जालसाजी का नया खुलासा

पीएनबी से फर्जी पत्रों के जरिए हासिल किए 6345 करोड़ रुपए

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में खुलासा किया है कि भारत का भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के स्वामित्व वाली कंपनियों ने तथाकथित तौर परफर्जी वचन पत्रों (लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग) और विदेशी साख पत्रों (फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट) के जरिए बैंक से 6344. 96 करोड़ रुपए की निकासी किया है। चोकसी पीएनबी घोटाला सामने आने से कुछ सप्ताह पहले जनवरी, 2018 में भारत से फरार हो गया था और तब से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था। पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा (मुंबई) में अधिकारियों ने मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान 165 वचन-पत्र (एलओयू) और 58 विदेशी साख पत्र (एफएलसी) जारी किये थे, जिनके आधार पर 311 बिलों में छूट दी गई। बिना किसी पाबंदी सीमा या नकदी सीमा के चोकसी की कंपनियों को ये पत्र जारी किए गए।एलओयू बैंक द्वारा उसके ग्राहक की ओर से किसी विदेशी बैंक को दी गयी गारंटी होती है। अगर ग्राहक विदेशी बैंक को पैसा नहीं लौटाता, तो देनदारी गारंटर बैंक की होती है। इन एलओयू के आधार पर एसबीआई-मॉरीशस, इलाहाबाद बैंक-हांगकांग, एक्सिस बैंक-हांगकांग, बैंक ऑफ इंडिया-एंटवर्प, केनरा बैंक-मनामा और एसबीआई-फ्रेंकफर्ट ने पैसा दिया था।

सीबीआई की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि 'जब आरोपी कंपनियों ने तथाकथित तौर पर फर्जी एलओयू और एफएलसी के आधार पर अर्जित राशि का भुगतान नहीं किया, तो पीएनबी ने विदेशी बैंकों को बकाया ब्याज समेत 6,344.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया।

येदियुरप्पा की कुर्सी से संकट टला

प्रदेश प्रभारी ने कहा-सूबे में सब ठीकठाक है

बेंगलुरु, (एजेंसी)। राज्य के तीन के दिन के दौरे पर गए कर्नाटक भाजपा के राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी की राज्य इकाई एकजुट है और मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है।

राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर आए सिंह ने कहा कि वह इस मुद्द पर पहले ही बोल चुके हैं। सिंह ने कहा कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता, मंत्री और विधायक एकजुट हैं। किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। सिंह ने शहर में आने पर पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पार्टी विधायकों से कहा है कि वे मीडिया में कोई बयान न दें और अगर उनकी कुछ चिंताएं हैं तो व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व से बात करें। उन्होंने विधायकों से कहा कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करें।

बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने की निषाद पार्टी के नेताओं से मुलाकात, आगामी विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा

नई दिल्ली । बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर चर्चा की. नड्डा ने ट्वीट कर कहा, ''आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और लोकसभा सांसद प्रवीण निषाद से मुलाकात की.''

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने एक बार फिर मजबूत सामाजिक समीकरण तय करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना दल (एस) और निषाद पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की थी.

छोटे दलों से हाथ मिला रही बीजेपी- विभिन्न जातिगत आधार वाले छोटे दलों के साथ भगवा दल की हाथ मिलाने की कोशिश उसकी उसी रणनीति का हिस्सा है जिसने उसे 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दिलाई थी. पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा से लंबी मुलाकातें की थी.

इन मुलाकातों के बाद से योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज हैं. अगले साल के शुरू में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि इनमें से चार-उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसकी सरकारें हैं.

सभी विवादों का हल नियमों के तहत शांति से होना चाहिए

चीन से तनाव के बीच राजनाथ सिंह बोले

नई दिल्ली ■ एजेंसी

एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सभी विवादों का हल बातचीत से और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के तहत शांति-पूर्वक होना चाहिए। रक्षा मंत्री बुधवार को एशियान डिफेंस मिनेस्टर्स मीटिंग (एडीएमएम) प्लस को संबोधित कर रहे थे। चीन भी इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को होने वाले खतरों का मुकाबला पुराने और घिसे-पिटे तरीकों से नहीं किया जा सकता है। साउथ चायना सी को लेकर भी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र कंनवेनशन ऑन लॉ ऑफ द सी के जरिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, समंदर के ऊपर से उड़ान भरने और बिना किसी रोक-टोक के वाणिज्य और कारोबार का सर्मथन करता है। समुद्री-आवाजाही इंडो-पैसेफिक क्षेत्र की शांति, स्थिरता, खुशहाली और विकास के लिए बेहद जरूरी है।

रक्षा मंत्री ने साउथ चायना सी विवाद पर कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट वार्ता ऐसे परिणाम की तरफ लेकर जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुकूल हो और उन देशों के कानूनी अधिकार और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जो इन चर्चाओं में हिस्सा नहीं हैं। रक्षा मंत्री ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि आतंकवाद और कट्टरपंथ आज पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे में सभी देश ऐसे देशों के खिलाफ एकजुट हों जो आतंक की सेंक्क्युरी बने हुए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद की फाईनिंसग पर भी लगाम कसी जानी चाहिए। रक्षा मंत्री ने सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया।

आठवीं एशियान बैठक में इस साल एशियान देश ब्रूनेई में हो रही है। रक्षा मंत्री ने साइबर-हमले और क्रि प्टोकरेंसी-थेफ्ट पर भी अपने विचार साझा किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए बेहद जरूरी है कि पूरी दुनिया का टीकाकरण हों। एडीएमएम-प्लस में दक्षिण-पूर्व एशिया के सभी 10 देशों (एशियान) के साथ-साथ भारत, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका भी शामिल हैं।

कानून मंत्री रविशंकर के निशाने पर ट्विटर, कहा- फ्री स्पीच के नाम पर कानून के पालन से नहीं बच सकते

नई दिल्ली । नए आईटी रूल्स को फॉलो नहीं करने को लेकर भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है. गाजियाबाद मामले के तूल पकड़ने के साथ ही अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए ट्विटर के खिलाफ कई ट्वीट किए हैं. प्रसाद ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कानून से बचा नहीं जा सकता है.

कानून की पालना से नहीं बच सकते- प्रसाद ने लगातार कई पोस्ट्स किए, जिनमें उन्होंने कहा कि अगर किसी विदेशी संस?था को लगता है कि वह खुद को भारत में अभिव?यक्ति की आजादी का झंडाबरदार बनकर कानून की पालना से खुद को बचा लेगी, तो ऐसी कोशिशें बेकार हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सच यह है कि 26 मई से प्रभाव में आई इंटरमिडियरी गाइडलाइंस के अनुपालन में ट्विटर असफल रहा है. ट्विटर को कई चांस दिए गए लेकिन उसने नए कानून का पालन नहीं करना ही चुना. प्रसाद ने आगे कहा कि गाजियाबाद में जो हुआ उसके बाद ट्विटर के एक्शन नहीं लेने से हैरानी है. इससे पता चलता है कि फेक न्यूज से उसकी लड़ाई में अस्थिरता है. प्रसाद ने कहा इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर संरक्षण प्रावधान का हकदार है. हालांकि, इस मामले का सामान्य तथ्य यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुए मध्यस्थ दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहा है. प्रसाद ने कहा कि हैरानी की बात है कि खुद को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के ध्वजवाहक के रूप में पेश करने वाला ट्विटर, जब मध्यस्थ दिशानिर्देशों की बात आती है तो जानबूझकर अवज्ञा का रास्ता चुनता है.

कोविशील्ड की दो डोज के बीच गैप बढ़ाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- वैज्ञानिक आधार पर हुआ फैसला

नई दिल्ली । सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दो डोज के बीच अंतर को 6-8 हफ्ते से बढ़ाकर 12-16 हफ्ते करने के बारे में तकनीकी विशेषज्ञों के बीच असंतोष का था, इसका स्वास्थ्य मंत्रालय ने खंडन किया है. मंत्रालय ने साफ किया है कि फैसला पूरी तरह वैज्ञानिक आधार और नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के सभी सदस्यों की सहमति से लिया गया है.

मंत्रालय ने कहा कि ये अंतर को बढ़ाने का फैसला एडेनो वेक्टर वैक्सीन के व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक कारणों पर आधारित है. बिना किसी असहमति के नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की कोविड-19 वर्किंग ग्रुप और स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमिटी की बैठकों में सदस्यों के साथ वैज्ञानिक आधार और डेटा पर पूरी तरह से चर्चा के साथ लिया गया.

टीकाकरण पर कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की 22वीं बैठक 10 मई हुई थी. डॉ एन के अरोड़ा, डॉ राकेश अग्रवाल, डॉ गगनदीप कांग, डॉ अमूल्य पांडा, डॉ जेपी मुलियाली, डॉ नवीन खन्ना, डॉ वीजी सोमानी और डॉ प्रदीप हलदरी शामिल थे. यूनाइटेड किंगडम (यूके) से रियल लाइफ एविडेंस के आधार पर वर्किंग ग्रुप ने कोविशील्ड वैक्सीन की दो डोज के बीच खुराक अंतराल को 12-16 सप्ताह तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया और वैज्ञानिक आधार पर सबकी सहमति से ये फैसला हुआ. कोविड-19 वर्किंग ग्रुप की इस सिफारिश को एनटीएजीआई की स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमिटी की 31वीं बैठक में चर्चा के लिए आगे बढ़ाया गया, जो 13 मई को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सेक्रेटरी डीएचआर और डीजी आइसीएमआर की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई थी. इसमें नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमिटी सिफारिश की कोविड-19 वर्किंग ग्रुप की सिफारिश के अनुसार, कोविशिल्ड टीके की दो खुराक के बीच कम से कम तीन महीने के अंतराल की सिफारिश की गई थी. दोनों बैठकों यानी कोविड-19 वर्किंग ग्रुप और एसटीएससी में, किसी भी सदस्यों में से किसी ने भी कोई असहमति नहीं दी. एक एजेंसी में अंतर बढ़ाने के फैसले में असहमति की खबर का मंत्रालय का खंडन किया है. साथ ये भी साफ किया कि जिन डॉक्टरों डॉ मैथ्यू वर्गीस, डॉ एम डी गुप्ते और डॉ जे पी मुलियाल का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, इन तीन सदस्यों में से किसी ने भी असहमति नहीं दी.

संक्षिप्त समाचार

अब नाटो ने चीन को बताया गंभीर चुनौती, बाइडन बोले- यूरोप की सुरक्षा अमेरिका की जिम्मेदारी

ब्रसेल्स । चीन के इर्द-गिर्द अमेरिका, जी-7 और यूरोप का शिकंजा कसता जा रहा है। अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) ने चीन को आक्रामक व्यवहार वाला और गंभीर चुनौती करार दिया है। नाटो के मुख्यालय पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूरोप की रक्षा को अमेरिका की पवित्र जिम्मेदारी बताया। कहा, पूरा यूरोप समझ ले कि अमेरिका मौजूद है। उसके रहते यूरोप को कुछ नहीं हो सकता है। नाटो का हमारे लिए बहुत महत्व है। बाइडन का यह वक्तव्य पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के उलट है जिन्होंने यूरोप की सुरक्षा से पीछे हट जाने की चेतावनी दी थी। इस मौके पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा, बाइडन का आना नए अध्याय की शुरुआत है। बाइडन ने कहा, रूस और चीन उस रास्ते पर नहीं चल रहे जिसकी हमने बीती सदी के आखिरी दशक में कल्पना की थी। दुनिया का मानना था कि दोनों देश उदारवादी लोकतंत्र के रास्ते पर चलेंगे और दुनिया से खतरा कम होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

अच्छा सहयोगी नहीं बन पाया चीन बाइडन ने कहा कि चीन हमारा अच्छा व्यापार सहयोगी नहीं बन पाया। इसके चलते नाटो के सदस्य देशों ने उसे साजिशों वाला प्रतियोगी करार दिया है। नाटो के महासचिव जेंस स्टॉटेनबर्ग ने कहा, चीन बाल्टिक सागर से लेकर अफ्रीका तक अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। इसलिए नाटो को सतर्क हो जाना चाहिए। चीन हमारे नजदीक आता जा रहा है। यहां तक कि अंतरिक्ष में भी। हमारे देशों में भी चीन बड़ा निवेश कर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है।

मिलकर जवाब देने की जरूरत- जेंस स्टॉटेनबर्ग ने कहा कि चीन दूरसंचार और बंदरगाहों के विकास जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है। हमें मिलकर उसे जवाब देने की जरूरत है। नाटो महासचिव ने यूक्रेन के नजदीक रूसी सैन्य जमावड़े पर भी चिंता जताई। ईयू सम्मिट में आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, बीजिंग के साथ रिश्ता रखने में खतरा और फायदा, दोनों हैं। यह हम सभी को दिमाग में रखना चाहिए। उल्लेखनीय है कि नाटो में 30 देश शामिल हैं जिनमें लगभग सभी यूरोपीय देश हैं। इससे पहले जी-7 देशों ने शिनजियांग में मानवाधिकारों और हांगकांग में लोकतंत्र की मांग को कुचलने तथा श्रमिकों की बुरी दशा को लेकर चीन को घेरा था। लंदन स्थित चीनी दूतावास ने सोमवार को इस पर विरोध व्यक्त किया। कहा कि अमेरिका और कुछ अन्य देशों का यह गलत आकलन है। चीन का बढ़ता कदम इन देशों को हजम नहीं हो रहा।

भारतीय सैन्य पुलिस में खुला नेपाली महिलाओं के लिए रास्ता, अब आसानी से रिक्त पदों पर कर पाएंगी अप्लाई

काठमांडू । भारतीय सेना ने पहली बार सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए रास्ता खोल दिया है। यानी अब नेपाली महिलाएं भी भारतीय सैन्य पुलिस में अप्लाई कर पाएंगी। रिक्त पदों पर आसानी से नेपाली महिलाओं की अब भर्ती हो पाएगी। बता दें कि यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती को रद करने की मांग उठ रही है। सेना का कहना है सेना में नेपाली युवाओं का दायरा बढ़ाने की लगातार जरूरत है। ऐसे में पुरुष और महिलाओं की भर्ती होना चाहिए। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सेना में पात्र नेपाली महिलाओं को ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा करने के संदर्भ में एलान किया है। इस घोषणा के साथ ही निश्चित मानदंड निर्धारित किए गए हैं, लेकिन उन बच्चों को भी कुछ छूट दी है जिनके माता-पिता भारतीय सेना में सेवा के दौरान शहीद हुए थे। मानदंड के अनुसार, जिन्होंने 10 वीं कक्षा पास की है और जिनकी आयु 16 से 21 वर्ष के बीच है या जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ है और जिनकी लंबाई 152 सेमी से अधिक है। वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तय की गई है। नोटिस के अनुसार, वीर नारी के रूप में वर्गीकृत लोग 30 साल तक आवेदन करने के पात्र हैं। मानदंड को पूरा करने वालों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए अंबल, लखनऊ, जबलपुर, पुणे, बेलगाम और शिलांग में भेजा जा सकता है। मानदंड के अनुसार, पूर्व भारतीय सेना के बच्चे जिनके पिता ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। उन्हें लिखित परीक्षा में 20 के वजन और अनुग्रह अंक में छूट प्रदान की जाएगी। नेपाल और भारत के बीच संधि के मुताबिक, भारतीय सेना में एक अलग गोरखा रेजिमेंट है और लाखों से अधिक नेपाली नागरिक भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर सेवा कर चुके हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान नेपाली युवाओं की भर्ती शुरू हुई थी।

कनाडा में मुस्लिम परिवार को ट्रक से कुचलने के मामले में आरोपित 20 वर्षीय पर लगा आतंकवाद का चार्ज

टोरंटो । कनाडा के ओंटारियो में पिछले हफ्ते रविवार रात एक ट्रक चालक द्वारा पाकिस्तानी मूल के एक परिवार को कुचल दिया था। नथानिएल वेल्टमैन नामक 20 वर्षीय चालक के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, इसमें अब आतंकवाद से संबंधित आरोप भी चालक के खिलाफ लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने इसे घृणा का कृत्य बताते हुए आतंकवादी कृत्य भी कहा था। अभियोजकों ने सोमवार को कहा कि चालक पर आतंकवाद से जुड़े आरोप भी लगा दिए गए हैं। पहले वेल्टमैन पर चार लोगों की हत्या और एक हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। इस घटना में एक किशोरी और वृद्धा समेत चार लोगों की मौत हो गई जबकि नौ वर्षीय एक लड़के का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, मरने वालों में दो महिलाएं, एक पुरुष और एक नाबालिग लड़की शामिल है। पुलिस सर्विस सुपरिटेंडेंट पॉल वाएट के मुताबिक, संदिग्ध शख्स और मुस्लिम परिवार में पहले कभी कोई संपर्क नहीं रहा है। कनाडा पुलिस ने इसे मुस्लिम परिवार को नियोजित तरीके से निशाना बनाया जाना कहा है। वहीं, खुद पीएम ट्रूडो पिछले हफ्ते मंगलवार की शाम एक शोक सभा में शामिल हुए जहां हजारों लोग मौजूद थे। ये शोक सभा एक मुस्लिम परिवार ने रखी थी। पुलिस के मुताबिक उनके परिवार के चार लोगों की हत्या पूर्वनियोजित तरीके से की गई थी। इस शोक की घड़ी में पूरा समाज एक साथ खड़ा दिखाई दिया। बताया जाता है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ सभी लोग शाम के वक्त सैर के लिए निकले थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मृतकों के धर्म की वजह से उन्हें निशाना बनाया। आरोपित को लंदन की मस्जिद से कुछ ही दूरी पर हिरासत में लिया गया था। शोक सभी के दौरान ट्रूडो ने कहा कि यह एक शैतानी काम था लेकिन आज यहां के लोगों की रोशनी, अफजल के परिवार के जीवन की रोशनी हमे हमेशा अंधेरे से आगे निकलने के लिए प्रेरणा देगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया की उनकी सरकार बिना किसी भी तरह की देर किए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

मुस्लिम परिवार की हत्या के बाद पीएम ट्रुडो ने देश में इस्लामोफोबिया से मुकाबले पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह इस घटना से विचलित हो गए हैं। इस्लामोफोबिया के लिए हमारे किसी भी समुदाय में जगह नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घटना की निंदा करते हुए कहा था कि आतंकी कारनामे से पता चलता है कि पश्चिम के देशों में इस्लामोफोबिया पांव पसार रहा है।

पाक सेना प्रमुख बाजवा ने अफगानिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपने जनरलों से तैयार रहने को कहा

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंगलवार को अपने शीर्ष जनरलों से भू-रणनीतिक स्थितियों के मद्देनजर अफगानिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा, कार्यशील सीमा और अफगानिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सैन्य तैयारियों के उच्च मानक बनाए रखने को कहा। दो दिवसीय 78वें फार्मेशन कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले जनरल बाजवा को अफगान शांति प्रक्रिया के लिए पाकिस्तान के सार्थक समर्थन और सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए किए जा रहे कड़े कदमों के बारे में बताया गया।

सेना ने कहा कि प्रतिभागियों को मौजूदा भू-रणनीतिक वातावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियों और उभरते खतरों के जवाब में अपनी रणनीति के बारे में जानकारी दी गई।

अंतरिक्ष में मानव मिशन को तैयार चीन, कल रवाना होंगे तीन एस्ट्रॉनॉट्स, पांच वर्षों में ऐसा पहला मिशन

बीजिंग । चीन अपने नए स्पेस स्टेशन के लिए तीन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए तैयार है। देश की स्पेस एजेंसी के मुताबिक गुरुवार की सुबह इन्हें स्पेस शिप शेंझू-12 से ज्यूकान सेटेलाइट लॉन्च सेंटर रवाना किया जाएगा। ये वहां पर करीब तीन माह तक रहेंगे। चीन की मेंड सपेस एजेंसी के डायरेक्टर के सहायक जी किमिंग ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी है। उनके मुताबिक अंतरिक्ष की ओर रवाना होने वालों में नी हेशेंग, लियु बोमिंग और टेंग होंग्बो शामिल हैं। ये तीनों चीन के अंतरिक्ष में बन रहे स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। चीन अपने इस पहले मानव मिशन को सत्ताधारी पार्टी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सौ वर्ष पूरे होने के मौके पर भेज रहा है। ऑर्बिट में प्रवेश के साथ ही स्पेस शिप स्पेस स्टेशन के कोर मॉड्यूल त्यानहे से मिल जाएगा।

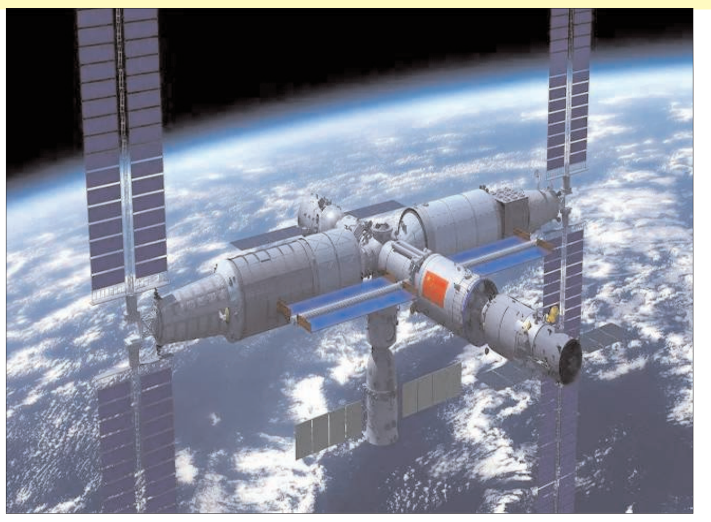

चीन अपने इस पहले मानव मिशन के लिए लॉन्ग मार्च 2एफ केरियर रॉकेट का इस्तेमाल करने वाला है। इसमें ईंधन भरने का काम शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के कोर मॉड्यूल त्यानहे का निर्माण 29 अप्रैल को शुरू किया था। चीन अपने इस स्पेस स्टेशन को आने वाले दो में विभिन्न मिशन के जरिए नई तकनीक से सुसज्जित करना चाहता है। ये स्पेस स्टेशन फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन इस वर्ष के अंत तक ये स्टेशन बन कर तैयार हो जाएगा। चीन के मेंड स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस के डायरेक्टर यांग लिवी जो अक्टूबर 2003 में शेंजू-5 क्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए थे, का कहना है कि पहले तीन महीने एस्ट्रॉनॉट्स वहां पर तीन महीने रुककर विभिन्न काम को अंजाम देंगे। इनमें स्टेशन की रिपेयर और उसकी मेंटेनेंस भी शामिल है। इस स्पेस स्टेशन के बनने तक चीन की अगले वर्ष तक 11 स्पेस मिशन भेजने की योजना है।

इसमें तीन मॉड्यूल के लिए चार कार्गो स्पेश शिप, चार मानव मिशन शामिल हैं। यांग का कहना है कि इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री केबिन से बाहर जाकर कंस्ट्रक्शन मिशन, स्पेस क्राफ्ट की मेंटेनेंस का काम भी करेंगे। धीरे-धीरे इन सभी काम को रोजाना के रुटिन में लाया जाएगा और इनका समय भी बढ़ाया जाएगा। चीन के इस स्पेस स्टेशन में रोबोटिक आर्म भी लगी है जिसको लेकर अमेरिका ने आपत्ति जताई थी कि ये सब कुछ मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। ये रोबोटिक आर्म करीब 15 मीटर लंबी है, जो विभिन्न काम में उपयोग लाई जा सकती है। चीन के मेंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के प्रमुख डिजाइनर झोऊ जियानपिंग का कहना है कि एस्ट्रॉनॉट्स वहां पर रोबोटिक आर्म के साथ स्टेशन को बनाने में मदद करेंगे। इसका इस्तेमाल वो जरूरत के मुताबिक मेंटेनेंस के दौरान भी करेंगे। अमेरिका कमांड के कमांडर जेम्स डिकींसन का कहना है कि चीन भविष्य में दूसरे देशों की सेटेलाइट को पकड़ने के लिए इस तरह के मिशन को अंजाम देने पर तुला है। उनके मुताबिक इसको लेकर अमेरिका की चिंता स्वाभाविक है। उनका ये भी कहना है कि चीन अंतरिक्ष में लगातार अमेरिका के साथ प्रतियोगिता कर रहा है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अमेरिका की नासा, रूस की रोस्कोमॉस, जापान की जेक्सा, यूरोपीयन स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी शामिल है।

कैलिफोर्निया में वैक्सीन जैकपॉट, जानें दस विजेताओं को मिलेगी कितनी धनराशि

लॉस एंजेल्स । कैलिफोर्निया में वैक्सीन लॉटरी के दस विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया। वैक्सीन जैकपॉट के जरिए घोषित विजेताओं में से प्रत्येक को 15 लाख रुपये की धनराशि बतौर इनाम दिए जाएंगे। राज्य में कोरोना वायरस सख्ती को खत्म करने के क्रम में गवर्नर गेविन न्यूसम ने मंगलवार को यूनिवर्सल स्टुडियोज में वैक्सीन की खुराक ले चुके कैलिफोर्निया के दस लोगों को ईनाम देने की घोषणा की है। दरअसल लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के क्रम में यहां वैक्सीन लेने के बाद पुरस्कृत करने का प्रोग्राम 'Vax for the Win' चलाया गया।

लॉस एंजेल्स में नर्स कोरडोवा राज्य की पहली नागरिक हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराक पिछले साल दिसंबर में ली थी। उन्होंने कहा कि यह उनके करियर का सबसे बुरा फेज है जब इतनी मौतों का सामना करना पड़ा। 22 मिलियन लोगों में से उन दस विजेताओं के नामों की घोषणा हुई जो कम से कम वैक्सीन की एक डोज भी ले चुके हैं। बता दें कि 2019 के अंत में चीन के वुहान में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। इसके दो-तीन माह बाद ही 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया। कोरोना संक्रमण के कारण सबसे बुरा हाल अमेरिका का रहा। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया में पूरी तरह पाबंदियों को हटाने से पहले अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने के क्रम में इस तरह की योजनाओं को लाया गया। कैलिफोर्निया ऐसा पहला राज्य नहीं है, जहां वैक्सीन लगाने के बदले में इनामी राशि की घोषणा की गई है।

दस वर्ष बाद पहली बार मिलेंगे बाइडन और पुतिन, तनातनी के बीच जानें- क्या है बातचीत का एजेंडा

जिनेवा । विश्व की दो महाशक्तियों के बीच बुधवार को जिनेवा में एक बेहद खास मुलाकात होने वाली है। ये दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस हैं। काफी लंबे समय से चली आ रही तनातनी के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली ये मुलाकात कई मायनों में खास है। आपको बता दें कि इन दोनों के बीच 10 मार्च 2011 को मास्को में आखिरी मुलाकात हुई थी। हालांकि उस वक्त बाइडन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, और पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान मुलाकात के दौरान दोनों के के ही पद बदल चुके हैं।

आपको यहां पर ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने जहां 20 जनवरी 2021 से राष्ट्रपति का पदभार संभाला है वहीं व्लादिमीर पुतिन अगस्त 1999 से ही रूस के राष्ट्रपति हैं। देश और दुनिया में उनकी गिनती एक ताकतवर नेता के रूप में होती आई है। पुतिन और बाइडन के बीच आज होने वाली मुलाकात के बीच इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर इन दोनों के बीच बातचीत का एजेंडा क्या होगा। आपको बता दें कि बीते कुछ वर्षों में अमेरिका और रूस के बीच जो खटास पैदा हुई है उसकी एक नहीं कई बड़ी वजह हैं। इनमें से एक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करना भी है, जिसको काफी अहम मुद्दा माना जा रहा है।

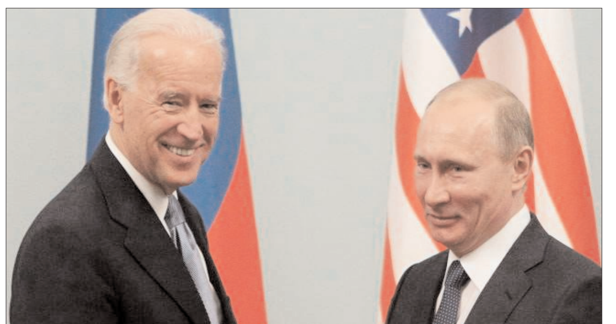

इसके अलावा अमेरिकी एजेंसियों और निजी कंपनियों पर किए गए साइबर अटैक के लिए भी रूसी राष्ट्रपति को ही जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति पुतिन के सामने उनके विरोधी नेताओं को जहर देकर मारने की कोशिश करने का भी मुद्दा उठा सकता है। पुतिन के घोर विरोधी नेता एलेक्सी नवलनी के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर अमेरिका समेत कई देश रूस के खिलाफ हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में पूर्व रूसी एजेंट और उनकी बेटी को नर्व एजेंट से मारने की कोशिश के लिए साजिश रचने का आरोप पुतिन पर ही लगा था। नवलनी की गिरफ्तारी और उसके बाद हुए प्रदर्शनों को दबाने और इसके लिए बल प्रयोग करने पर भी अमेरिका और अन्य देश पुतिन के खिलाफ हैं। अमेरिका कई बार रूस पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है।

दोनों देशों के बीच हथियार एक बड़ा मुद्दा है। हाल के कुछ समय में रूसी की रक्षा प्रणाली एस 400 इसकी एक बड़ी वजह बनी है। अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस की इस प्रणाली को कोई भी देश खरीदे। इसको लेकर रूस और अन्य देशों पर दबाव भी डाला जा रहा है। तुर्की और भारत पर भी ये दबाव डाला गया है। हालांकि दोनों ही देश इससे पीछे हटने से साफ इनकार कर चुके हैं। इसके अलावा सीरिया में पुतिन का सरकार को समर्थन और वहां पर ताबड़तोड़ हमले करना साथ ही सीरियाई फौज को मदद करना हमेशा से ही अमेरिका को नापसंद रहा है। ऐसा ही कुछ यूक्रेन और लीबिया में भी है। बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों में भी काफी हद तक गिरावट देखी गई है। पुतिन जहां अमेरिकी जेलों में बंद अपने नागरिकों की रिहाई की बात कर सकते हैं वहीं बाइडन की रूसी जेला में बंद अपने नागरिकों के लिए ऐसी ही मांग कर सकते हैं।

सिंध में पैसे देकर कोई कुछ भी कर सकता है, प्रांत में नहीं है सरकार जैसी कोई चीज- चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुल्जार अहमद ने सिंध में लगातार सार्वजनिक जगहों पर हो रहे अतिक्रमण और निर्माण को लेकर प्रांतीय सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि सरकार कनाडा के इशारे पर काम कर रही है। देश के प्रधान न्यायधीश ये कटाक्ष कोर्ट के समक्ष आई एक सिविल मिसलिनिएस एप्लीकेशन पर सुनवाई के दौरान किए हैं। इसमें कोर्ट का ध्यान खाली पड़ी जमीन पर लैंड माफिया के कब्जे की तरफ दिलाया गया था। इसमें राजनीतिक पार्टियों की सहभागिता भी बताई गई थी। जस्टिस गुलजार ने सिंध में बन रहे शाहराह ए फैसल टावर के निर्माण से जुड़े एक मामले में कहा कि कनाडा में बैठा यूनुस मेमन प्रांतीय सरकार को कनाडा से चला रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार ऐसे नाले की सफाई नहीं कर सकती है तो वो प्रांत कैसे चलाएगी। जस्टिस गुल्जार यहीं पर नहीं रुके बल्कि उन्होंने कहा कि सरकार का कराची की जनता से जुड़े मसलों से कोई लेना देना नहीं है बल्कि बिल्डिंग कंट्रोल ऑथरिटी को पैसे देकर जो मन में है वो करिए। सिंध में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।

कोर्ट ने प्रांत के एडवोकेट जनरल से जानना चाहा कि सरकार कैसे इस बात को पुख्ता कर सकती है कि वो इन तमाम चीजों पर निगरानी रख सकती है। ये सब काम केंद्र की सरकार करने को मजबूत है लेकिन क्या प्रांतीय सरकार ये सब कुछ कर पाने में असमर्थ है। यदि ऐसा है तो वो राज्य को कैसे चला सकती है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने एक वर्ष पहले इस तरह के गंदे नालों को साफ करने का आदेश दिया था लेकिन सरकार हर बार कोई न कोई समसया बताकर समय टालती रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि मेमन जैसे लोग कम नहीं हुए हैं बल्कि लगातार बढ़ रहे हैं। प्रांत में कई जगहों पर सर्विस रोड तक का अतिक्रमण किया जा चुका है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।

जस्टिस गुल्जार ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रांतीय सरकार को एजूकेशन प्रोजेक्ट के तहत ढाई खरब से अधिक रुपये दिए गए थे, जिसका काम 2014 में शुरू होकर 2017 में खत्म हुआ था। इसी तरह से डेढ़ खबर रुपये पानी के लिए तरस रहे लोगों के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाने के लिए दिए गए थे। इस बात की जिम्मेदारी ऑथरिटी को है कि वो शहर के विकास और समस्याओं के हल के लिए क्या फैसला लेती है।

ऑथरिटी कोई बजट पास करती है तो उसका इस्तेमाल लोगों के हक के लिए नहीं किया जाता है। ये बेहद गंभीर मसला है। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्रालय को भी हालिया कुछ रेल हादसों केलिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने पीएम से अपील की कि इसको सुधारने के लिए तेजी से काम किया जाए। उन्होंने रेलवे मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई।

पाकिस्तान :13 साल की लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कर कराया गया निकाह, न्याय के लिए भटक रहा पिता

इस्लामाबाद । पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला एक 13 वर्षीय इसाई लड़की का है। लड़की के पिता का आरोप है कि एक मुस्लिम लड़के ने लड़की का अपहरण कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और फिर जबरदस्ती उससे शादी कर ली। यह घटना पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर में हुई है। लड़की के पिता के अनुसार, अपहरणकर्ता एक मुस्लिम है जिसने लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता के पिता अपने परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आरिफ टाउन के एक दर्जी शाहिद गिल ने कहा कि उनके पड़ोसी ने उनकी 13 वर्षीय बेटी को उनकी मेकअप एक्सेसरीज की दुकान पर सेल्सगर्ल के रूप में काम पर रखने की पेशकश की थी। हालांकि गिल ने अपनी बेटी को दुकान पर काम पर भेजने से मना कर दिया था।

उन्होंने कहा कि अपहरणकर्ता लगातार उनसे मदद की मांग करता रहा। शाहिद ने कहा कि घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण बाद में उन्होंने अपनी बेटी को पड़ोसी की दुकान पर काम करने की अनुमति दे दी। गिल ने कहा कि 20 मई को उनकी बेटी घर से गायब हुई थी बाद में पड़ोसियों से पता चला कि उन्होंने लड़की को अपहरणकर्ता

और कुछ अन्य पुरुषों एवं महिलाओं के साथ पिकअप ट्रक पर जाते हुए देखा था।

उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत वो फिरोजवाला पुलिस स्टेशन में करवा चुके थे और 29 मई को उस व्यक्ति और सात अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी एसआइ लियाकत ने कहा कि दो संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया लेकिन बाद में लड़की एक स्थानीय अदालत में पेश हुई। पुलिस अधिकारी के अनुसार, लड़की ने अदालत में कहा कि उसने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपनाने और बाद में अनुबंधित विवाह करने के लिए अपना घर छोड़ा था। उन्होंने कहा कि अदालत ने लड़की को उसके कथित पति के साथ जाने की अनुमति दे दी थी और पुलिस को मामला रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अदालत के आदेश का पालन किया।

हालांकि, लड़की के पिता गिल ने कहा कि उसकी बेटी साढ़े 13 साल की है और इसलिए अदालत को उसके धर्मांतरण और स्वेच्छा से शादी करने के उसके बयान को स्वीकार नहीं करना चाहिए। गिल ने कहा कि वह व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा था और उसके तीन बेटियां और एक बेटे सहित चार बच्चे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली गई और हो सकता है कि लड़की ने ऐसा बयान दबाव में दिया हो। उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण (नादरा) से उनकी बेटी की उम्र की पुष्टि करने और उन्हें न्याय प्रदान करने की मांग की।

अमेरिका स्थित सिंधी फाउंडेशन ने कहा है कि हर साल 12 से 28 साल की करीब 1,000 युवा सिंधी हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है, उनकी जबरन शादी की जाती है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पाकिस्तान ने कई मौकों पर राष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करने का वादा किया है। हालांकि, अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर हमले एक अलग कहानी बयान करते हैं।

यरुशलम के पुराने शहर के बाहर, पूर्वी यरुशलम के माध्यम से यहूदी अतिराष्ट्रवादियों द्वारा एक नियोजित मार्च से पहले भड़की झड़पों के दौरान इजरायली पुलिस अधिकारियों ने एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को हिरासत में लिया।

पाक की संसद में जमकर हुआ हंगामा, सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे पर फेंके बजट के दस्तावेज

इस्लामाबाद । पाकिस्तान की संसद में मंगलवार को लोकतांत्रिक मर्यादा उस वक्त तार-तार हो गई जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे को जमकर गालियां दीं और आधिकारिक बजट दस्तावेजों की प्रतियां एक-दूसरे पर फेंकीं। अफरातफरी और हंगामे एक महिला सदस्य घायल हो गई।

संसद के निचले सदन, नेशनल असेंबली का सत्र 2021-22 के बजट पर बहस करने के लिए बुलाया गया था। शुक्रवार को वित्त मंत्री शौकत तारिन ने बजट पेश किया था।

मंगलवार को जब विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने बजट पर बहस के लिए परंपरागत भाषण देने का प्रयास किया तो सत्ता पक्ष ने शोर-शराबा शुरू कर दिया।

कुछ ही समय में सदन एक युद्ध के मैदान में बदल गया जब कुछ सांसद आमने-सामने आ गए। इन लोगों ने एक-दूसरे को जमकर गालियां दीं और अंत में बजट दस्तावेजों की प्रतियां फेंकना शुरू कर दिया।

सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के नेता अली अवान का विपक्ष पर अपशब्द कहने का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीटीआई की कम से कम एक महिला सांसद मालेका बोखारी की आंख पर एक दस्तावेज लगने के बाद इलाज कराया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष शहबाज ने बाद में एक ट्वीट कर पीटीआई एक फासीवादी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश ने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा कि सत्ताधारी दल ने विपक्ष को दबाने के लिए किस तरह गुंडागर्दी और गालीगलौज का सहारा लिया।

सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पीएमएल-एन अशांति के लिए जिम्मेदार है क्योंकि इसके सदस्यों में से एक ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे पीटीआई के कुछ सदस्यों को गुस्से में प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

दिल्ली सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर पांच हजार हेल्थ असिस्टेंट तैयार करेगी : केजरीवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली सरकार ने पांच हजार युवाओं को हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए पांच हजार हेल्थ असिस्टेंट तैयार करेगी। पहली और दूसरी लहर के दौरान मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी देखी गई थी। इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। आईपी यूनिवर्सिटी 9 मेडिकल इंस्टिट्यूट में इन्हें नर्सिंग, पैरामेडिक्स, होम केयर, ब्लड प्रेशर मापने, वैक्सीन लगाने आदि की बेसिक ट्रेनिंग दिलवाएगी। सीएम ने कहा कि हेल्थ असिस्टेंट, डॉक्टर और नर्स के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे और खुद से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। इनकी मदद लेकर डॉक्टर अधिक कुशलता पूर्वक काम कर पाएंगे और मरीजों की देखभाल भी काफी अच्छे से हो सकेगी। इसके लिए 12वीं कक्षा पास 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा 17 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 28 जून से 500-500 के बैच में इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। मैं समझता हूं कि इस निर्णय से संभावित तीसरी लहर को लेकर चल रही हमारी तैयारी को काफी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की। सीएम ने कहा कि जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तीसरी लहर अगर आती है, तो उससे दिल्ली को बचाने की तैयारी की जा रही है। संभावित तीसरी लहर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पिछले कुछ दिनों में मैं कई अस्पतालों में भी गया। दिल्ली में ऑक्सीजन के कई नए प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन के सिलेंडर और ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक समेत कई सारी तैयारियां संभावित तीसरी लहर को लेकर की जा रही है। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है, तो जैसा हमने पहली और दूसरी लहर में देखा कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 5 हजार हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना बनाया है। इनको तकनीकी भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट भी कहते हैं।

मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल ने कहा कि 5 हजार युवाओं को यह ट्रेनिंग दी जाएगी। दो-दो हफ्ते की यह ट्रेनिंग आईपी यूनिवर्सिटी दिलवाएगी और दिल्ली के 9 प्रमुख मेडिकल इंस्टिट्यूट हैं, जहां पर उन लोगों को बुनियादी प्रशिक्षण (बेसिक ट्रेनिंग) दिया जाएगा। यह 5 हजार जो हेल्थ असिस्टेंट या कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट बनेंगे, वे डॉक्टर्स और नर्सेस के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे और अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर उनको जो काम देंगे, नर्स उनको जो काम देंगी, वे वही काम करेंगे। इनको बेसिक नर्सिंग में, पैरामेडिक्स में, लाइफ सेविंग में, फर्स्ट एड में, होम केयर आदि में इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें बुनियादी चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे-ऑक्सीजन कैसे मापते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, टीका कैसे लगाते हैं, वैक्सीनेशन अगर करनी है, तो वह कैसे करते हैं। पेशेंट केयर में डायपर बदलने, कैथेटर, सैंपल कलेक्शन करना है, कंसंट्रेटर कैसे काम करता है, सिलेंडर कैसे करते हैं, मास्क कैसे लगाना है, आदि चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मान लीजिए कि हमने एक बहुत बड़ा कोविड-19 केयर सेंटर बनाया तो, वहां पर अगर डॉक्टर के साथ इस तरह के कई सारे असिस्टेंट लगा दिए जाएंगे, तो वे कुशलता पूर्वक काम कर पाएंगे और मरीज की देखभाल भी काफी अच्छे तरीके से हो पाएगा। हम इन पांच हजार लोगों को प्रशिक्षित करके छोड़ देंगे। जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी, तब इनको बुलाया जाएगा और जितने दिन इनसे काम करवाया जाएगा, उतने दिन की इनको तनख्वाह दी जाएगी। 17 जून से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और 28 जून से इन लोगों की ट्रेनिंग चालू होगी। 500-500 लोगों के बैच में इनकी ट्रेनिंग होगी। अर्थात एक बैच 500 लोगों का होगा। दो हफ्ते की यह ट्रेनिंग होगी और दो हफ्ते बाद फिर दूसरा बैच चालू हो जाएगा चालू हो जाएगा। इस तरह कुल 5 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग लेने के लिए जो लोग 12वीं कक्षा पास हैं, वह लोग पात्र हैं और इनकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और पहले आओ, पहले पाओ के अधार पर लोगों को लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इससे हमारी जो संभावित तीसरी लहर की तैयारी है, उसको काफी मजबूती मिलेगी। अगर तीसरी लहर आती है, तो उसके लिए मैन पावर तैयार होगी। मैं फिर से उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तीसरी लहर न आए। लेकिन इंग्लैंड और यूके से खबर आ रही है कि वहां पर तीसरी लहर आ गई है। इसलिए हमें भी दुनिया भर में जो कोरोना के डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं करनी है।

मॉनसून के लिए और लंबा हुआ इंतजार

नई दिल्ली। देश के पूर्वी हिस्से में लगातार बारिश जारी है और मॉनसून आगे बढ़ते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आ गया है। इसके बाद अगले एक से दो दिन में ही दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी, जिसके लिए 15 जून का अनुमान लगाया गया था। लेकिन अब तक दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक नहीं दी है। यही नहीं मौसम विभाग ने अब अपने अनुमान में तब्दीली करते हुए दिल्ली में मॉनसून के 7 से 10 दिन तक की देरी से आने की बात कही है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस सप्ताह भी दिल्ली-एनसीआर समेत आसपास के इलाकों को झुलसती गर्मी और उमस झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग के रीजनल फोरकास्ट सेंटर के हेड कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, हम अब मॉनसून के आने में 7 से 10 दिन की देरी का अनुमान लगा रहे हैं। पश्चिम यूपी में मॉनसून की कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम में महापौर के पद भार सम्भालने के बाद श्याम सुन्दर अग्रवाल को बधाई देते कार्यकर्ता।

राज्य सरकारों की मदद के बजाय उनके कामों में टांग अड़ा रही केंद्र सरकार : सिसोदिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले लोगों की पुष्टि कर उनके परिवारों को सहायता राशि देने के लिए बनाई गई कमिटी को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी दी और केंद्र सरकार के इस गैर जिम्मेदार रवैये पर सवाल उठाए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पॉजिटिव केसों की संख्या तेजी से बढ़ी और अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में कुछ लोगों की मौत भी हुई। इसी दिशा में दिल्ली सरकार द्वारा एलान किया गया कि ऑक्सीजन की कमी से मरे प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को सरकार 5 लाख रुपये की राशि मुआवजे के तौर पर देगी। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक कमेटी का गठन किया जो अस्पतालों के डेटाबेस द्वारा इस बात की पुष्टि करेंगे कि मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है ताकि मृतक के परिजनों को जल्द से जल्द मुआवजे की राशि दी जा सके।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ये बहुत दुख की बात है कि केंद्र सरकार ने इस कमेटी को खारिज कर दिया है। जबकि कमेटी कोर्ट के आदेश पर गठित की गई थी। उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भी कोई राज्य सरकार कुछ अच्छा करने का प्रयास करती है चाहे वो महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल या दिल्ली हो, केंद्र सरकार उनके काम में अड़ंगा जरूर लगाती है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं किया और ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का भट्टा बिठा दिया। और जब जिम्मेदार सरकार के नाते दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों के परिजनों की मुआवजा देकर मदद करना चाह रही है तो केंद्र सरकार इसमें टांग अड़ा रही है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपील करते हुए केंद्र सरकार को गैर जरूरी हस्तक्षेप बंद करने का आग्रह किया। और केंद्र सरकार द्वारा की जा रही बचकानी हरकत बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि उनके द्वारा चुनी हुई काम करें लेकिन केंद्र सरकार उन्हें काम करने से रोक रही है और जनता के हितों के हर काम में हस्तक्षेप कर उसे रोक रही है।

दिल्ली की तीनों नगर निगमों में नए महापौर और उप महापौर निर्विरोध निर्वाचित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की तीनों नगर निगम के लिए महापौर, उप-महापौर और स्थायी समिति सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में महापौर राजा इकबाल सिंह और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में महापौर का पद श्याम सुंदर अग्रवाल ने संभाला तो वहीं दक्षिण दिल्ली निगम के महापौर मुकेश सूर्यान चुने गए। उत्तरी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के चुनाव सिविक सेंटर में और पूर्वी निगम के चुनाव पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र स्थित निगम मुख्यालय में सम्पन्न हुए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर पद के चुनाव के लिए पक्ष तथा विपक्ष के पार्षद सुबह 11 बजे सिविक सेंटर के अरुणा आसिफ अली सभागार में पहुंचे।

नये महापौर की चुनाव प्रकिया शुरू होने से पहले उत्तरी निगम में कोरोना योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। उसके बाद निगम सचिव ने चुनाव प्रकिया की घोषणा की। महापौर, उप-महापौर और स्थायी समिति सदस्य के पदों पर निर्विरोध चुना गया। महापौर पद के लिए राजा इकबाल सिंह के नाम की घोषणा कर सभी औपचारिकताएं पूरी की गई और उप-महापौर के लिए अर्चना को चुना गया। उनके पदभार ग्रहण किया तो उसके बाद पार्षद बधाई देने डायस पर पहुंच गए और पुष्पगुच्छ भेंट करने की रस्म पूरी की। महापौर और उप-महापौर चुनाव के बाद स्थायी समिति के तीन सदस्यों के रूप में जोगी राम जैन (भाजपा) विजय भगत (बीजेपी) तथा राजीव यादव (आप) को निर्वाचित किया गया। महापौर के लिए निर्विरोध चुनाव हुआ। यहां भी सत्ता और विपक्ष के पार्षद समय पूर्व ही पहुंचने शुरू हो गए थे। यहां निगम सचिव ने श्याम सुंदर अग्रवाल का नाम महापौर पद के लिए घोषित किया जबकि उप-महापौर के लिए किरन वैद्य को चुना गया। स्थायी समिति के लिए वीर सिंह पंवार, हिमांशी पांडेय तथा आप पार्टी की मोहिनी को निर्विरोध निर्वाचित हुए। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में महापौर पद के लिए मुकेश सूर्यान और उप-महापौर के लिए पवन शर्मा को निर्विरोध चुना गया जबकि स्थायी समिति सदस्य के लिए इंद्रजीत सहरावत, पूनम भाटी तथा कांग्रेस से सुरेश कुमार को चुना गया। कांग्रेस के सुरेश कुमार और आप पार्टी के प्रवीन के बीच वोटिंग हुई थी, लेकिन दोनों को बराबर मत मिले और बाद में पर्ची से ड्रा निकाला गया जिसमें सुरेश कुमार स्थायी समिति सदस्य के लिए चुने गए।

ड्रग कंट्रोलर विभाग ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को आक्सीजन वैन मामले में भेजा नोटिस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रदेश भाजपा ने पिछले दिनों कोरोना पीड़ितों के लिए जो ऑक्सीजन वैन अभियान चलाया था, उसपर दिल्ली सरकार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता को कानूनी नोटिस भेजा है। इस तरह दिल्ली में ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी रोकने में नाकाम केजरीवाल सरकार न्यायालय के आदेशों का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है।

केजरीवाल सरकार के राजनीतिक दबाव में आज दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर विभाग ने दिल्ली प्रदेश भाजपा द्वारा गत माह जनसेवा हेतु चलाई गई आक्सीजन वैन को कालाबाजारी गतिविधियों के साथ जोड़कर कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर की चार सदस्यीय टीम ने आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के कार्यालय में आ कर लगभग दो घंटे तक पूछताछ की और मात्र 24 घंटे से भी कम का समय देते हुए कल दोपहर 2 बजे तक एक प्रश्नावली का जवाब देने को कहा है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि भाजपा सेवा को समर्पित पार्टी है और कोविडकाल में सेवा ही संगठन हमारा ध्येय है और हम किसी भी राजनीतिक प्रताड़ना के भय से सेवा कार्य बंद नही करेंगे उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली सरकार के नोटिस का कानूनी जवाब तो देंगे ही साथ ही राजनीतिक प्रताड़ना के इस मामले को जन मानस के बीच भी लेकर जायेंगे।

दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के करीबी जूडो कोच को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई सागर धनखड़ की हत्या के मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच ने सुभाष नाम के एक जूडो कोच को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सागर की हत्या के वक्त मौके पर मौजूद था और उसपर मारपीट करने का भी आरोप है। पुलिस हत्थे चढ़े इस आरोपी के बारे में पुलिस को ओलंपियन सुशील कुमार और गिरफ्तार साथियों से पूछताछ के बाद दौरान मिली तो पुलिस ने इसे धर दबोचा है। इस मामले में पुलिस अबतक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तारी कर चुकी है। इस मामले में मुख्य आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार है। सुशील को मंडोली जेल में रखा गया है। वह 25 जून तक न्यायिक हिरासत में है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी सुभाष को गुप्त सूचना पर दिल्ली के किराड़ी इलाके में स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। वारदात के बाद से ही वह फरार था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना नंबर भी ऑफ कर रखा था। उसकी तलाश में जुटी पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के जरिये उसके करीबी नेटवर्क का पता लगा कर उसके साथियों के जरिये उसपर नजर रखे हुए थी। इस बीच मंगलवार को पुलिस को यह सूचना मिली कि वह अपने घर आने वाला है तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी प्रिंस को घटना वाले दिन ही दबोच लिया था, जबकि इसके बाद सुशील कुमार और अजय को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। वहीं असौदा-बवाना गैंग के चार अन्य बदमाशों भूपेंद्र उर्फ भूपी, मोहित उर्फ भोली, गुलाब उर्फ पहलवान और मनजीत उर्फ चुन्नीलाल को गिरफ्तार किया था। फिर शुक्रवार को विरेंदर उर्फ विंदर और रोहित करोर को पुलिस ने दबोचा। वहीं 11 जून को सोनीपत के अनिरुद्ध नाहरी नाम के एक पहलवान की गिरफ्तारी हुई। अब इस मामले में 11 वें आरोपी जूडो कोच सुभाष को 15 जून को दबोचा गया है। मुख्य आरोपी सुशील कुमार है। सुशील को मंडोली जेल में रखा गया है।

दक्षिणी दिल्ली निगम में स्थायी समिति में सदस्य पद पर हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत

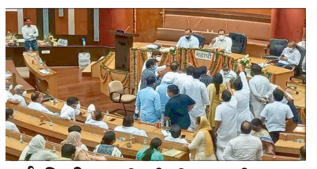

नई दिल्ली। दक्षिणी निगम की सदन की बैठक में विपक्षी दलों ने हंगामा कर दिया। दरअसल, स्थायी समिति में सदस्य पद के लिए चुनाव पर विवाद हो गया। काफी हंगामे के बाद स्थायी समिति में सदस्य पद पर कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया। विवाद खत्म करने के लिए ड्रा के बाद पर्ची डाली गई। जिसे सफाई कर्मचारी से निकलवाया गया। जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी का नाम निकला। विपक्ष में होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार की हार हो गई। बता दें कि स्थायी समिति में सदस्य पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा के दो उम्मीदवारों को जीत मिली। जबकि तीसरे पद पर कांग्रेस व आम आदमी पार्टी (आप) में मुकाबला रहा। चार सदस्यों ने मतदान के दौरान वरीयता रोमन में लिख दी थी। जिसको लेकर विवाद हुआ।

दिल्ली पुलिस की टीम संबित पात्रा टूलकिट केस में की पूछताछ

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी के कथित टूलकिट को लेकर एक ट्वीट किया था। बाद में ट्विटर ने उसे मैनिपुलेटेड मीडिया घोषित कर दिया। इस मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम ने इस साल 31 मई को मामले के संबंध में माहेश्वरी से पूछताछ करने के लिए बेंगलुरु की यात्रा की थी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस की जांच न केवल अमेरिका स्थित मूल कंपनी के साथ ट्विटर इंडिया के संबंधों की एक स्पष्ट तस्वीर स्थापित कर रही है, बल्कि भारतीय कानून लागू करने वाली संस्थाओं को गुमराह करने के लिए कॉरपोरेट पर्दा का जटिल जाल का भी खुलासा कर रही है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजकर इस बारे में जानकारी मांगी थी कि कांग्रेस के कथित टूलकिट पर संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया के रूप में क्यों टैग किया गया था। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक से पूछताछ करने का निर्णय दिल्ली पुलिस को उसके नोटिसों पर अपमानजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद लिया गया। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने मनीष माहेश्वरी के दरवाजे तक जाने की पेशकश की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह मामले के संबंध में सभी प्रासंगिक सवालों का जवाब दे सके। जवाब में, ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी ने अपना

बेंगलुरु पता दिया और कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल होंगे मामले के तथ्यों से परिचित सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा, ट्विटर के दरवाजे पर ही हेरफेर शुरू होता है। ट्विटर को अपने कर्मचारियों की फैक्ट चेक शुरू करनी चाहिए। माहेश्वरी ने दिल्ली पुलिस को बताया कि ट्विटर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद उन्हें कंपनी के निदेशकों के बारे में जानकारी नहीं थी। माहेश्वरी, जिन्हें कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में भी जाना जाता है, ने कहा कि उन्होंने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से ट्विटर इंडिया के संस्थागत ढांचे के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त की। दिल्ली पुलिस ट्विटर इंडिया के प्रमुख द्वारा इस आश्चर्यजनक स्वीकारोक्ति की भी जांच कर रही है कि, देश में कंपनी का सबसे वरिष्ठ कर्मचारी होने के बावजूद, उसे अपनी टीम के बारे में बहुत कम जानकारी है।

दिल्ली में राशन की बर्बादी को लेकर अब कांग्रेस ने भी उठाई आवाज, एलजी से जांच समिति गठित करने की मांग

नई दिल्ली। सरकारी राशन की बर्बादी पर भाजपा के बाद कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जयकिशन ने बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर इस प्रकरण में एक जांच समिति गठित करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि गरीबों के मुंह का निवाला छीनने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी दृष्टि से माफी के लायक नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि एक तरफ आप सरकार लंबे समय से घर घर राशन योजना को लागू करने पर आमादा है। जबकि दूसरी तरफ वह उचित दर दुकानों पर भी ढंग से राशन वितरण नहीं करवा पा रही। सालों से लोगों के राशन कार्ड नहीं बने और बिना राशन कार्ड लोगों को राशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। स्थिति यह हो गई है कि घंटों लाइन में लगकर भी जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पा रहा जबकि स्कूलों और गोदामों में राशन पड़ा पड़ा सड़ रहा है।

जयकिशन ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके करीबों को बांटने के लिए जो अनाज खरीदा था, उसका सड़ना तो एक अपराध से कम नहीं है। जनता का पैसा जनता के ही काम नहीं आ पाया। जो राशन प्रवासी कामगारों को बांटने के लिए केंद्र सरकार ने दिया, उसका भी दिल्ली सरकार की अनदेखी से खराब होना शर्म की बात है। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी, विभागीय मंत्री इमरान हुसैन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी बराबर के दोषी हैं। इसलिए इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जाए तथा दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

संपादकीय

माकूल पहल का बीतता वक्त

सरकार के दावों और मीडिया खबरों पर यकीन करें, तो कोरोना की दूसरी लहर भी अब खत्म होने को है। सवाल पूछे जाने लगे हैं कि बाजार कब खुलेंगे, कितने खुलेंगे? हम कब बाहर निकलकर खुले में घूम पाएंगे और जिंदगी कब सामान्य या पहले जैसी हो पाएगी? बहुत जल्दबाजी है, व्यापारियों को, आम लोगों को और सरकारों को भी, कि कब इस बला के टलने के पक्के संकेत आएं और कितनी तेजी से लॉकडाउन हटाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर दौड़ाने का इंतजाम किया जाए। यह जरूरी भी है, क्योंकि साल भर से ज्यादा वक्त हो चुका है। लोगों के पास काम नहीं है, कमाई नहीं है। खर्च कम करते-करते भी अब न सिर्फ गरीब, बल्कि मध्यवर्ग के परिवार भी इस हाल में आ चुके हैं कि अब पाई-पाई का हिसाब लगाना पड़ रहा है। बहुत से लोग तो कंगाली की चपेट में हैं। नौकरियां चली गई हैं या फिर तनख्वाह नहीं मिल रही है। यही हाल छोटे व्यापारियों का भी है और छोटी-मोटी नौकरी करने वालों का भी।

ऐसे में, उन परिवारों की सोचिए, जिनका कमाने वाला सदस्य कोरोना की भेंट चढ़ गया और अब बाकी लोगों को न सिर्फ इस दुख का सामना करना है, बल्कि रोजी-रोटी का इंतजाम भी करना है। एक-एक परिवार का हिसाब लगाना तो मुश्किल है, पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) का कहना है कि जब से कोरोना संकट शुरू हुआ, तब से देश में नौकरीपेशा लोगों की गिनती में भारी गिरावट हुई और इसमें सुधार के आसार नहीं दिख रहे। कोरोना के ठीक पहले देश में कुल 40.35 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। तब से अब तक सबसे अच्छी स्थिति दिसंबर और जनवरी में आई, जब यह गिनती वापस 40 करोड़ पर पहुंची, लेकिन अब यह गिनती 39 करोड़ पर है। इनमें से भी करीब 7.3 करोड़ या 7.4 करोड़ लोग हैं, जिनके पास पक्की या कच्ची नौकरियां हैं। यानी, जिन्हें हर महीने बंधी तनख्वाह मिलती है। कोरोना के पहले ऐसे लोगों की गिनती करीब 8.5 करोड़ थी। समस्या की गहराई में जाने के लिए एक और आंकड़ा देखने से मदद मिलेगी। सीएमआईई ने अपने सर्वे में लोगों से पूछा कि एक साल पहले के मुकाबले आज उनकी कमाई का क्या हाल है? सिर्फ तीन फीसदी लोगों ने कहा कि उनकी आमदनी पिछले साल से बेहतर है। 55 प्रतिशत लोगों ने तो साफ-साफ कहा कि उनकी आमदनी एक साल पहले के मुकाबले कम हो गई है, और बाकी का कहना था कि कमाई न बढ़ी है, न घटी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप महंगाई को हिसाब में जोड़ लें, तो देश के 97 फीसदी लोगों की कमाई एक साल में बढ़ने के बजाय कम हो गई है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है, और इसके साथ ही सवाल उठता है कि इस हालत से उबरा कैसे जाएगा? पिछले साल जब पहली बार लॉकडाउन लगा, तब एक झटके में सब कुछ बंद भी हो गया, पर बाद में सब कुछ उतनी ही तेजी से वापस भी आता हुआ दिखा। इस बार अनेक जानकारों ने कहा है कि लॉकडाउन के दूसरे दौर का अर्थव्यवस्था पर असर उतना नहीं होगा, जितना पहली बार हुआ था। मगर सच तो कुछ और है। दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक बार्कलेज ने हिसाब लगाया है कि मई के महीने में लॉकडाउन का एक-एक हफ्ता भारत को आठ अरब डॉलर, यानी करीब 58 हजार करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा रहा है। बार्कलेज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी फिर घटा दिया है और अब उसके हिसाब से 2021-22 में देश की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार 9.2 फीसदी ही रह जाएगी। उसके अर्थशास्त्री राहुल बाजोरिया और श्रेया सोढ़ानी का कहना है कि हालांकि, कोरोना की दूसरी लहर अब उतार पर है, लेकिन इससे हुआ आर्थिक नुकसान काफी बड़ा है। बीमारी को रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाए गए, वे बहुत कड़े थे, और दूसरी तरफ टीकाकरण की रफ्तार धीमी है।

टीके लगने की रफ्तार कम होने से मध्यम अवधि में देश की तरक्की के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। खासकर उस सूरत में, अगर देश को कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ जाए। बार्कलेज का कहना है कि ऐसी बुरी हालत में देश की अर्थव्यवस्था को 42.6 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में, भारत की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार और गिरकर इस वित्त वर्ष में 7.7 प्रतिशत ही रह सकती है। बड़ी फिक्र की बात यह है कि इस वक्त किसी भी स्तर पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो आर्थिक मोर्चे पर इस मुसीबत से निकलने का कारण बन सके। कुछ कंपनियों ने दरियादिली दिखाई है और कोरोना के शिकार अपने कर्मचारियों को एक साल या ज्यादा का वेतन देने का एलान किया है। टाटा समूह ने तो ऐसे लोगों के परिवारों को उनकी पूरी नौकरी के दौर तक तनख्वाह, कंपनी के घर और मेडिकल सुविधाएं जारी रखने का फैसला किया है। पर ज्यादातर कंपनियों की हालत यह है कि वे दो-तिहाई क्षमता पर काम कर रही हैं। ऐसे में, वे खुद नया पैसा लगाने या अर्थव्यवस्था को धक्का देने की हालत में नहीं हैं। जब तक बाजार में नई मांग न आए, तब तक उनके लिए ऐसा करने का तुक भी नहीं है। अब एक ही उम्मीद बचती है। वह है सरकार। सरकार ने पिछले साल बड़ा भारी राहत पैकेज देने का एलान किया था। हालांकि, उसमें वास्तविक राहत कितनी थी, इस पर आज तक विवाद चल रहा है। लेकिन इस बार सरकार की तरफ से कुछ होता हुआ दिखा नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि अगर इस वक्त सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, तो यह मुसीबत काफी खतरनाक मोड़ ले सकती है। सीआईआई प्रेसिडेंट ने कहा भी है कि सरकार को अब बड़े पैमाने पर नोट छापकर गरीबों को सीधे पैसा बांटना चाहिए और उन सारे कारोबारों को राहत देनी चाहिए, जिन पर इस महामारी की गंभीर मार पड़ी है, और जहां रोजगार पर बुरा असर हुआ है। उनका कहना है कि वह वक्त आ गया है, जब सरकार को सहारा देकर अर्थव्यवस्था को मुसीबत से बाहर निकालने का काम करना होगा। अगर अब यह नहीं किया, तो फिर कब?

प्रवीण कुमार सिंह

कोरोना वायरस की उत्पत्ति का रहस्य, ज्यादा संहारक होती है अदृश्य जंग

सिर्फ अमेरिका ही नहीं, लद्दाख बॉर्डर पर अपने एशियाई प्रतिद्वंद्वी भारत को भी वह कोरोना वायरस के रूप में एक अदृश्य जंग में उलझाए रखना चाहता है। पर यह सब चीन ने कहां से शुरू किया, इस सवाल के जवाब में वुहान स्थित उसकी प्रयोगशाला पर ही नजर जाती है। वैसे तो इसकी पुष्टि चीन को ही करनी है कि इस वायरस की शुरुआत वुहान स्थित फ्रेश सी-फूड मार्केट से हुई और इसकी उत्पत्ति में चमगादड़ों और सांप के मांस से तैयार की गई डिश (भोजन) है या फिर इसमें कुछ योगदान वुहान स्थित उस प्रयोगशाला का है, जिसमें खतरनाक वायरसों पर प्रयोग किए जाते हैं।

मानव इतिहास बताता है कि इस धरती से युद्ध कभी खत्म नहीं हुए। हम शांति की जितनी अधिक कामना करते हैं, उतनी ही अधिक लड़ाइयां दुनिया के किसी न किसी हिस्से में चलती रहती हैं। कभी बम और मिसाइलें बरसाई जाती हैं, तो कभी छिपकर गोरिल्ला शैली के युद्ध छेड़े जाते हैं। इसमें विज्ञान और तकनीक की तरक्की ने नए किस्मों के हथियार बनाकर आग में और घी डालने का काम किया है। जैसे, माइक्रोवेव तरंगें, साइबर जंग और जैविक युद्ध आदि। बताया जाता है कि आज से करीब सौ साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों द्वारा एंथ्रेक्स और ग्लैंडर्स के जीवाणुओं का जो प्रयोग किया गया था, वह विकसित जैविक हथियारों का ही नमूना था। अब नया मामला कोरोना वायरस की उत्पत्ति का है। पिछले लगभग डेढ़ साल से पूरी दुनिया में इस पर चर्चा जारी है कि आखिर कोरोना वायरस आया कहां से है। शक की सूई ज्यादातर समय चीन और वुहान स्थित उसकी प्रयोगशाला पर जाकर ही अटकती रही है। इधर एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावे के साथ कहा गया है कि जब खुद चीन ने कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया था, उससे एक महीने पहले वुहान स्थित वायरोलॉजी लैब के शोधकर्ताओं को इसी वायरस की चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था।

इसी संदर्भ में अमेरिका का बाइडन प्रशासन इसकी जांच को लेकर अड़ गया है कि दुनिया को इसका पता चलना ही चाहिए कि इस घातक वायरस की उत्पत्ति के पीछे कहीं वास्तव में चीन ही तो नहीं है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, हम सभी के मन में यह सवाल उमड़-घुमड़ रहा है कि क्या सच में इस वायरस और इससे पैदा महामारी के पीछे चीन है। क्या उसी ने खुद को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए कोरोना वायरस के रूप में जैविक युद्ध की शुरुआत की, ताकि वह आर्थिक रूप

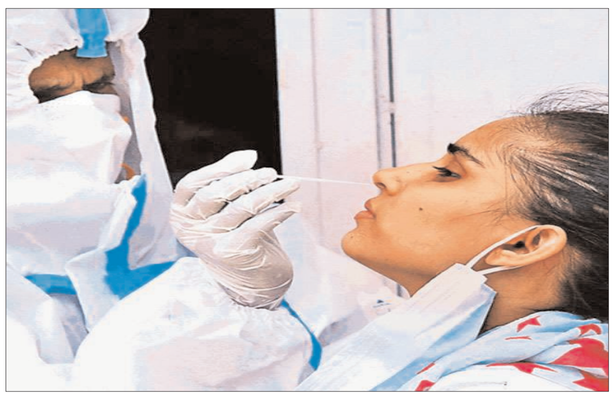

से ताकतवर होकर उभरे और अपना वर्चस्व कायम कर ले। चर्चाएं और आशंकाएं कई हैं, पर इसमें ताजा बदलाव 'वर्ल्ड हेल्थ असेंबली' की ओर से हो सकता है।

अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से 'वर्ल्ड हेल्थ असेंबली' में इस पर विचार हो रहा है कि क्या ऐसी कोई वैश्विक महामारी संधि तैयार हो सकती है, जिसमें दुनिया को जैविक युद्ध छेड़ने की आशंकाओं की रोकथाम हो सके और ऐसा करने वाले गुनहगार देश को दंडित किया जा सके। अगर ऐसा हो सका तो कोविड-19 जैसी भयानक महामारी से बचने के लिए देशों को कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जा सकेगा। पर इस पूरी कवायद को शुरू करने के पीछे जो असली सवाल है, वह यही है कि क्या चीन ही कोरोना का जनक देश है। और क्या उसी ने अपने शातिर दिमागों का इस्तेमाल कर दुनिया पर यह जैविक युद्ध थोप दिया है।

चीन पर संदेह करने वालों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे थे। राष्ट्रपति रहते हुए किए गए अपने एक ट्वीट में उन्होंने कोरोना को चाइनीज वायरस कहकर सीधे तौर पर इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा दिया था। उनके अलावा, तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी इसे 'वुहान वायरस' कहा था। इसे चाइनीज वायरस कहने से ट्रंप प्रशासन का आशय यह था कि चीन ने इस वायरस को अमेरिका से बदला लेने के लिए अपनी प्रयोगशाला में पैदा किया, लेकिन वह इस पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। ऐसे में बेकाबू चाइनीज वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। चीन की सरकार वायरस के इस नामकरण से काफी नाराज हुई। इसके बाद चीन के तमाम इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी खबरें आने लगीं कि इस वायरस की पैदावार के पीछे असल में अमेरिका का हाथ है। इन आरोपों के मुताबिक कोरोना से पैदा हुई महामारी अमेरिकी मिलिट्री जर्म वॉरफेयर प्रोग्राम के जरिये फैली है। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस के संदर्भ में हो रही बयानबाजी को इन मुल्कों के वर्चस्व की जंग के तौर पर भी देखा गया। कहा गया कि ऐसा इन दोनों देशों में खुद को महाशक्ति के रूप बनाने या कायम रखने की जंग के चलते हुआ। लेकिन अब एक बार फिर अमेरिका ने नए दावों के आधार पर चीन को आड़े हाथों लिया है।

अमेरिकी विदेश विभाग को प्राप्त हुए खुफिया दस्तावेजों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन ही कोरोना वायरस का जनक है। इन खुफिया दस्तावेजों का स्रोत ब्रिटिश अखबार 'द सन' है जिसने 'द ऑस्ट्रेलियन' के हवाले से बताया है कि चीन की वायरस में संलिप्तता की विस्फोटक जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग के हाथ लगी है। इस जानकारी के मुताबिक पीएलए यानी चीनी सेना के कमांडर ये कुटिल पूर्वानुमान लगा रहे थे कि किस तरह कोरोना वायरस के जरिये दुनिया की आर्थिक बर्बादी तय की जा सकती है और कैसे चीन का वर्चस्व कायम किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में ही चीनी सेना के कमांडर एक तीसरे विश्वयुद्ध का अंदाजा लगा रहे थे, जिसे जैविक हथियारों से लड़ा जाना है। इन कथित दस्तावेजों में यह उल्लेख भी है कि इस वायरस को कृत्रिम रूप से बदला जा सकता है और इसे इंसानों में बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु में बदला जा सकता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल एक ऐसे हथियार के रूप में किया जा सकता है जिसे दुनिया ने पहली बार कभी नहीं देखा है। जैविक युद्ध की बात हवा-हवाई नहीं है। इसका एक इतिहास भी है। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में मेसोपोटामिया के अस्सूर साम्राज्य के लोगों ने पानी पीने के कुओं में एक जहरीला कवक (फंगस) डालकर दुश्मन के असंख्य सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था। यूरोपीय इतिहास के अनुसार तुर्की व मंगोल साम्राज्य में संक्रमित पशु शरीरों को शत्रु राज्य के जल स्रोतों में डाल कर उन्हें संक्रमित कर दिया जाता था। पहले विश्व युद्ध (1914-18) के दौरान जर्मन सैनिकों ने एंथ्रेक्स जैसे जीवाणुओं के रूप में जैविक हथियारों के इस्तेमाल से आधुनिक युग की पहली जंग लड़ी थी। ऐसे में अब अगर चीन व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) में अमेरिका से पिछड़ने के बाद उसे सबक सिखाने के लिए कोरोना वायरस का इस्तेमाल कर रहा होगा, इस आशंका को लेकर ज्यादा संदेह नहीं रह जाता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, लद्दाख बॉर्डर पर अपने एशियाई प्रतिद्वंद्वी भारत को भी वह कोरोना वायरस के रूप में एक अदृश्य जंग में उलझाए रखना चाहता है। पर यह सब चीन ने कहां से शुरू किया, इस सवाल के जवाब में वुहान स्थित उसकी प्रयोगशाला पर ही नजर जाती है। वैसे तो इसकी पुष्टि चीन को ही करनी है कि इस वायरस की शुरुआत वुहान स्थित फ्रेश सी-फूड मार्केट से हुई और इसकी उत्पत्ति में चमगादड़ों और सांप के मांस से तैयार की गई डिश (भोजन) है या फिर इसमें कुछ योगदान वुहान स्थित उस प्रयोगशाला का है, जिसमें खतरनाक वायरसों पर प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन वुहान स्थित जैव प्रयोगशाला पी 4 को लेकर दुनिया भर के शक की एक और वजह बताई जा रही है। दावा है कि वुहान में जब न्यूमोनिया का पहला मामला नजर आया था, तो उससे कुछ दिन पहले ही चीन के उपराष्ट्रपति वांग किशान चुपचाप वहां (वुहान) पहुंचे थे। दावा किया गया कि वांग वहां जैविक हथियारों की योजना की प्रगति देखने गए थे। इस संबंध में जैविक हथियारों (बायोलॉजिकल वॉरफेयर) पर अध्ययन करने वाले इजरायल के एक पूर्व मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर का दावा है कि कोरोना वायरस को चीन की ही पी 4 लैब में तैयार किया गया।

केंद्रीयकृत राज्य-सत्ता के विकास के साथ सामंतवाद का पराभव हुआ, लेकिन आज तकनीकी परिवर्तन राज्य-सत्ता को कमजोर कर रहा

आइटी नियमों यानी इंफारमेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड रूल्स-2021 को लेकर भारत सरकार और ट्विटर एवं वाट्सएप के बीच टकराव विश्व पटल पर हो रहे बड़े परिवर्तन की नई कड़ी है। पिछले दो दशकों का तकनीकी विकास अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक व्यवस्था में भारी उथलपुथल का कारण बना है। इतिहास में तकनीकी क्रांति ही असली क्रांति साबित होती आई है, जो मानव समाज को परिर्वितत करती है और अपने अनुरूप नई विचारधारा, रजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती है। पिछली कुछ शताब्दियों में तकनीकी परिवर्तन पुरानी सामंतवादी व्यवस्था के पतन का कारण बना। कारखानों और उत्पादन की नई संरचना ने नए शहरों को निर्मित किया, आर्थिक शक्ति को ग्रामीण इलाकों, कृषि एवं जमींदारों से उद्योगपतियों और मध्यम-वर्ग को हस्तांतरित किया, जिससे राज्य की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई, जो आवागमन और संचार के बेहतर साधनों के साथ आधुनिक राष्ट्र-राज्यों की उत्पत्ति में परिलक्षित हुई। केंद्रीयकृत राज्य-सत्ता के विकास के साथ सामंतवाद का पराभव हुआ, लेकिन आज वही तकनीकी परिवर्तन राज्य-सत्ता को कमजोर कर रहा है और नई सामंतवादी व्यवस्था को जन्म दे रहा है, जिसे हम डिजिटल नव-सामंतवाद कह सकते हैं। इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जनित कंपनियां जैसे फेसबुक, एपल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन, जिन्हें बिग-टेक भी कहा जाता है, आज इतनी शक्तिशाली हैं कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन पांच कंपनियों के अलावा अनेक ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, जो बेहद शक्तिशाली बनती जा रही हैं। इनमें से एक ट्विटर भी है। डिजिटल नव-सामंतवाद के आधार-स्तंभ हैं- अप्रत्याशित कंप्यूटिंग शक्ति, बिग-डाटा और तेजी से उभरती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ, आर्थिक शक्ति का निजी हाथों में अत्यधिक केंद्रीयकरण और समाज को प्रभावित करने एवं अपने अनुसार ढालने की क्षमता। इनकी मनमानी ताकत आम नागरिकों को इनकी मर्जी पर निर्भर रहने को मजबूर कर रही है। इन नए डिजिटल सामंतों की शक्ति आज लोकतांत्रिक सरकारों और राज्य की शक्ति को भी अक्षम बनाने में समर्थ है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते लगातार अमेरिकी कानूनों, जैसे सेक्शन 230 में परिवर्तन करके इन कंपनियों के मनमाने व्यवहार पर रोक लगाने की बात की थी। यह खुली बात है कि इसके जवाब में इन कंपनियों ने ट्रंप के विरुद्ध चुनावी माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आज क्या बोला जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, लोग आपस में कैसे बात कर रहे हैं, सूचना प्रसारण कैसे हो रहा है, सूचना कहां एकत्र हो रही है और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, व्यापार एवं वाणिज्य कैसे हो रहा है, यह सब इन डिजिटल नव-सामंतवादी कंपनियों द्वारा निर्धारित हो रहा है। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इन सब का डाटा भी इन कंपनियों के पास जा रहा है। इसका उपयोग लोगों की पसंद के अनुसार निर्मित विज्ञापन दिखाने से लेकर राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने तक में किया जा रहा है। कभी सोचा है कि आपने वाट्सएप पर किसी वस्तु के बारे में बात की और फेसबुक पर उसी के विज्ञापन क्यों दिखने लगे? आप किसी स्थान पर गए और गूगल पर वहां की दुकानों के विज्ञापन क्यों दिखने लगे? कभी सोचा है कि ट्विटर, वाट्सएप इत्यादि मुफ्त क्यों हैं? क्योंकि वे नहीं, बल्कि आप इन कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, जिसे वे बेच रहे हैं। आज सत्ता का हस्तांतरण राज्य से इन डिजिटल नव-सामंतों की तरफ हो रहा है। हाल में गूगल ने ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश को गंभीर परिणाम भुगतने और व्यापार-निषेध की धमकी दी। इस धमकी का मकसद था कि ऑस्ट्रेलिया गूगल की मनमानी रोकने का कानून बनाने से बचे। इस धमकी के साथ ही यह संकेत किया गया कि सूचना-तंत्र का उपयोग ऑस्ट्रेलियाई सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने में किया जाएगा। भारत में भी ट्विटर और वाट्सएप जैसी कंपनियां प्रत्यक्ष तौर पर यही कर रही हैं।

नए आइटी नियमों के अनुसार बिग टेक कंपनियों को भारत के नियमों का पालन करना होगा, जैसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित समाग्री को हटाना। किसी भी भारतीय के संविधान-प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित न करना, जब तक कि कोई कानूनी आदेश न हो। जनता के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त करना, भारत के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए अनुपालन अधिकारी और एक नोडल अधिकारी को भारत में ही तैनात करना। इसके अलावा सरकार द्वारा कानूनी प्रक्रिया से दिए गए आदेश के अनुसार किसी जुर्म-आतंकवाद, अपहरण जैसी स्थिति में वारदात से संबंधित डाटा को सरकार को उपलब्ध कराना। आज तक दसियों करोड़ यूजर होने के बाद भी किसी भी बिग टेक कंपनी का भारत में कोई ऑफिस और अनुपालन अधिकारी नहीं है। ऐसा भारत को समुचित टैक्स देने से बचने के लिए है। ट्विटर ने पिछले साल अनुमानत- मात्र 15 लाख का टैक्स दिया।

बड़े देशों का दायित्व

ब्रिटेन के कॉर्नवाल में चल रही जी-7 देशों की तीन दिवसीय शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को ऑनलाइन शिरकत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया सहित भारत को बतौर मेहमान इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक जिन हालात में हो रही है, उन्हें देखते हुए कोई आश्चर्य नहीं कि महामारी के चंगुल से दुनिया को जल्द से जल्द मुक्त कराने का लक्ष्य इसके अजेंडे में सबसे ऊपर है। चाहे सवाल वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का हो या क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने की ओर बढ़ने का या विभिन्न देशों के बीच संबंधों के समीकरण को ज्यादा सामंजस्यपूर्ण और तर्कसंगत बनाने का- इन तमाम महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में गंभीर विचार-विमर्श तभी हो सकता है जब मनुष्य समाज के सिर पर लटकी मौत की तलवार हटे।

जैसा कि पिछले एक डेढ़ साल के अनुभव से साफ हो जाता है कि संक्रमण दर और मौत की संख्या को एक बार या दो बार काबू कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। दूसरी, फिर तीसरी और उसके बाद चौथी लहरों का खतरा बना ही रहेगा। इसका स्थायी समाधान दुनिया की ज्यादातर आबादी को टीकाकरण के दायरे में लाना ही हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद धीमी है। अभी तक दुनिया की छह फीसदी से कुछ ही ज्यादा आबादी पूरी तरह वैक्सिनेशन के दायरे में आ सकी है। भारत में तो यह प्रतिशत साढ़े तीन से भी कम है। अच्छा संकेत यह है कि जी-7 के देश इस मसले पर गंभीरता दिखा रहे हैं। अमेरिका ने 50 करोड़ डोज वैक्सीन अन्य देशों को देने की बात कही है। ब्रिटेन ने 10 करोड़ डोज वैक्सीन डोनेट करने की घोषणा की है। अन्य देश भी ऐसा रुख दिखाएं और उस पर अमल करें तो कम से कम इस मोर्चे पर तेजी आने की उम्मीद की जा सकती है।

बैठक की अहमियत इस बात में भी है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जो बाइडेन की यह पहली विदेश यात्रा है और इस बात पर सबकी नजर रहेगी कि पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की खास शैली के प्रभावों से निकलने के बाद अमेरिकी कूटनीति किस तरह के संकेत देने वाली है। प्रसंगवश, राष्ट्रपति ट्रंप ने जी-7 को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए इसे विस्तारित करके जी-10 या जी-11 का रूप देने का सुझाव दिया था। तमाम चुनौतियों के बीच भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जी-7 जैसे मंचों को सांकेतिकता से ऊपर उठाना आज की बड़ी जरूरत है। अगर इस दिशा में बात बढ़ती है तो यह इस बैठक की सफलता ही कही जाएगी।

सभी चिकित्सा पद्धतियां मिलकर कोविड को परास्त करने में जुटीं

समस्या चिकित्सा पद्धति के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित छिपे व्यावसायिक हितों से है। दुर्भाग्य से इलाज से जुड़े बिजनेस मॉडल मानवीय जीवन से जुड़े किसी भी संस्थान से कहीं अधिक नुकसानदेह हैं। आज हर क्षेत्र में भरोसे का संकट है, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में पैदा होने वाली अविश्वसनीयता इसलिए सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि यह सीधे हमारे जीवन-मरण से जुड़ी है। अब यह आज के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों को तय करना है कि उनके लिए मनुष्य को निरोगी रखने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है या चिकित्सा पद्धतियों की स्वघोषित श्रेष्ठता? मानवता का यह आह्वान सिर्फ एलोपैथी ही नहीं, आयुर्वेद समेत हर चिकित्सा पद्धति के प्रवर्तकों से है।

कुछ दिनों पहले योगगुरु बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर दिए गए बयान के बाद जारी आरोप-प्रत्यारोप का दौर फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा है। बाबा रामदेव ने उपचार की एलोपैथी पद्धति को विशेष रूप से कोरोना के संदर्भ में बेअसर करार दिया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) और फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस पर कड़ा एतराज जताया। आखिरकार बाबा रामदेव ने अपने शब्द वापस लिए। इसमें कोई दो मत नहीं कि योग और आयुर्वेद की पुनर्स्थापना में बाबा रामदेव की अग्रणी भूमिका है। बावजूद इसके बिना किसी वैज्ञानिक आधार के जिस प्रकार उन्होंने एक चिकित्सा पद्धति को सवालों के कठघरे में खड़ा कर दिया, वह न्यायसंगत नहीं था। हालांकि बाबा रामदेव ने इस विषय पर खेद प्रकट कर अपनी उदारता का परिचय दिया, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच जारी गैर जरूरी उकसावे में वे मुद्दे पीछे छूट रहे हैं, जिनके समाधान से मानवीय स्वास्थ्य को गुणवत्ता देने का साझा मार्ग खोजा जा सकता है।

चिकित्सा की हर पद्धति की अपनी कुछ विशेषताएं और सीमाएं होती हैं। एलोपैथी पर हम इस कदर निर्भर हो चुके हैं कि आज इसके बिना मानव जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। असहनीय पीड़ा और आपात स्थिति में आयुर्वेद के बड़े पैरोकार भी नजदीकी एलोपैथ डॉक्टर की शरण में जाते हैं। चिकित्सा पद्धतियों के मध्य सहयोग की जगह टकराव तब सामने आया है, जब सभी चिकित्सा पद्धतियां मिलकर कोविड को परास्त करने में जुटी हैं।

कोरोना की महात्रासदी को हराने में किसी एक पैथी का योगदान है, यह सोचना ज्ञान की एक पूरी विधा का तिरस्कार करने जैसा है। एलोपैथी के साथ ही आयुर्वेद के डॉक्टर भी अनवरत मानवता की सेवा कर रहे हैं। आज शायद ही कोई घर हो जहां तुलसी, गिलोय, त्रिकटु (पीपल, सोंठ, काली मिर्च), मुलेठी, अश्वगंधा, मेथी, आंवला, शहद, एलोवेरा से तैयार औषधियों का सेवन न किया जाता हो।

करोड़ों लोग यदि कोरोना संक्रमण से बचने में सफल हुए हैं तो उसके पीछे एलोपैथिक दवाओं तथा इलाज के साथ आयुर्वेदिक औषधियां सर्वसुलभ संजीवनी साबित हुई हैं। आयुष मंत्रालय की पहल पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की निगरानी में तैयार आयुष-64 के साथ ही मुलेठी क्वाथ, महासुदर्शन घन वटी, संशमनी वटी आदि दवाओं से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। यहां तक की आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग के लिए अलग प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश भी जारी किए। गत एक वर्ष में आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात में दोगुनी वृद्धि इस बात को प्रमाणित करती है कि भारत ही नहीं विश्व में आयुर्वेद की धाक जम रही है।

एलोपैथी और आयुर्वेद को परस्पर विरोधी चिकित्सा पद्धति करार देने की जगह हमें उनके स्वरूप को समझना होगा। आयुर्वेद का तो दर्शन ही रोग पूर्व बचाव (प्रिवेंटिव हेल्थ केयर) पर आधारित है। हजारों वर्ष प्राचीन आयुर्वेद शरीर में उत्पन्न दोष की पहचान तथा उसके निवारण की प्रक्रियाओं पर काम करता है। पूरा आयुर्वेद आहार, विहार और औषधि पर आधारित है। एलोपैथी के छात्र जिस तरह एमबीबीएस करते हैं, उसी तरह आयुर्वेद के छात्र बीएएमएस की पढ़ाई कर चिकित्सा क्षेत्र में कदम रखते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में उन्हें वात, पित्त, कफ के संतुलन की वैज्ञानिक विधियों से अवगत कराया जाता है। ये छात्र धातु एवं मल साम्यता का भी अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत शरीर में रस, रक्त, मांसपेशियों, अस्थि मज्जा एवं स्वेद, मूत्र, मल में साम्यता कैसे स्थापित हो, इसका वृहद अध्ययन किया जाता है। एलोपैथी और आयुर्वेद समेत सभी चिकित्सा पद्धति में चिकित्सकीय जांच के आधार पर ही रोगियों का इलाज किया जाता है। खून या पेशाब की सामान्य जांच हो या सीटी स्कैन और एमआरआइ वह एलोपैथी ही नहीं, आयुर्वेद में भी समान रूप से सहायक हैं। बैचलर ऑफ आयुर्वेद इन मेडिकल सर्जरी (बीएएमएस) और फिर आयुर्वेद में ही मास्टर ऑफ सर्जरी (एमएस) कर लोगों का इलाज करने वाले चिकित्सक जरूरत पड़ने पर मेडिकल जांच की विधियों का उसी तरह अनुप्रयोग करते हैं, जैसे एलोपैथिक डॉक्टर कर रहे हैं।

दुनिया का शायद ही कोई कोना हो, जहां आयुर्वेद पर शोध कार्य प्रगति पर न हो। पड़ोसी देश चीन को ही ले लीजिए, वहां एलोपैथी के साथ-साथ रोगों के पूर्व निदान के लिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन (टीसीएम) लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। उन्हें इस बात का भी संकोच नहीं है कि टीसीएम भारतीय आयुर्वेद की ही देन है। जापान में लंबे समय से लोकप्रिय रेकी चिकित्सा विधि को भी आयुर्वेद की देन माना जाता है। एशियाई महाद्वीप के कई देशों में तो आयुर्वेद के महाविद्यालय और संस्थान तेजी से खुल रहे हैं। क्या हम ऐसी विज्ञान सम्मत परंपरा के साथ अब तक न्याय कर सके हैं, जिसके संवाहक अपने पूर्वज रहे हों।

वस्तुत- देखा जाए तो समाज किसी चिकित्सा पद्धति के विरोध में नहीं है। समस्या चिकित्सा पद्धति के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित छिपे व्यावसायिक हितों से है। दुर्भाग्य से इलाज से जुड़े बिजनेस मॉडल मानवीय जीवन से जुड़े किसी भी संस्थान से कहीं अधिक नुकसानदेह हैं। आज हर क्षेत्र में भरोसे का संकट है, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में पैदा होने वाली अविश्वसनीयता इसलिए सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि यह सीधे हमारे जीवन-मरण से जुड़ी है। अब यह आज के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों को तय करना है कि उनके लिए मनुष्य को निरोगी रखने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है या चिकित्सा पद्धतियों की स्वघोषित श्रेष्ठता? मानवता का यह आह्वान सिर्फ एलोपैथी ही नहीं, आयुर्वेद समेत हर चिकित्सा पद्धति के प्रवर्तकों से है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

वन नेशन, वन राशन कार्ड : बिहार के 10,938 लोगों ने दूसरे प्रदेशों में लिया जनवितरण का राशन

पटना । पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि जून 2020 में लांच की गई वन नेशन, वन राशन कार्ड स्कीम के तहत नौ महीने में बिहार के 10,938 लोगों ने दूसरे प्रदेशों में अपना राशन उठाया है। इसके साथ ही बिहार के कुल 1.75 करोड़ राशनकार्ड धारियों में से 45 लाख परिवारों ने अपने पैतृक निवास से इतर बिहार के अन्य जिलों व शहरों में राशन उठा कर इस योजना का लाभ लिया। इस स्कीम को सबसे पहले लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अप्रैल में 3,249 और मई महीने में 2,438 लोगों ने दूसरे राज्यों में राशन लिया है। दमन और दीव में काम करने गए 2,523 और महाराष्ट्र में 1,918 लोगों ने इस योजना का लाभ लिया। इसी प्रकार अप्रैल और मई महीने में बिहार में रह रहे दूसरे राज्यों के 327 प्रवासियों ने भी राशन का उठाव किया। इससे उन्हें काफी सहूलियत हुई है। पिछले वर्ष राशन कार्ड के लिए आवेदन देने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ 30 लाख लोगों को यहां राशनकार्ड निर्गत किया गया है। अब कोई भी राशनकार्डधारी किसी भी दूसरे राज्यों में प्रवास के दौरान राशन का उठाव कर सकता है। प्रवासी अपने राशन का एक हिस्सा दूसरे राज्यों में तो शेष हिस्सा अपने राज्य में भी उठा सकते हैं। दूसरे राज्यों में जितना राशन का उठाव होगा अगले महीने उतने राशन की उनके राज्य में कटौती कर ली जाएगी। क्या है वन नेशन, वन राशन कार्ड स्कीम - गौरतलब है कि एक देश, एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष की थी। इसका उद्देश्य था कि राशन कार्डधारी अपने कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से में अपने हिस्से का राशन उठाव कर सकेंगे।

मूसलाधार बारिश बढ़ा नदियों का जलस्तर, कैमूर में बाढ़ की आशंका पर हो रही इस तरह की तैयारी

भभुआ । मानसून के दस्तक देने के बाद जिले में मौसम लगातार खराब चल रहा है। प्रतिदिन जिले में बारिश हो रही है। इससे जिले से होकर गुजरी नदियों पर बने पुल भी लगातार बारिश से क्षतिग्रस्त हो रहें हैं। उधर लगातार बारिश से जिले की नदियों व नहरों में पानी भी आ गया है। लेकिन, अभी मौसम का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा। आसमान में बादल छाए रह रहे हैं और सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। इसके चलते अभी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन भी पुरी तरह तैया है। जिले में आठ प्रशिक्षित गोताखोरों के साथ आठ गश्ती दल का गठन किया गया है। कैमूर में 21 नाव भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा 400 पॉलीथिन सीट उपलब्ध है। साथ ही बाढ़ आने पर पशुचारा, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरने व खाने-पीने की व्यवस्था की प्रक्रिया पुरी कर ली गई है। गठित गश्ती टीम को किसी भी विशेष परिस्थिति में तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए गठित टीम कार्य करेगी। बता दें कि कैमूर जिले में भारी बारिश होने पर कर्मनाशा, सुवरन और दुर्गावती नदी के साथ अन्य पहाड़ी नदियों का जल स्तर बढ़ कर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है। लेकिन जिले में सबसे अधिक बाढ़ की संभावना नुआंव, रामगढ़ और दुर्गावती प्रखंड के गांवों में रहती है। इन प्रखंडों में कुछ गांव नदी के किनारे या आसपास हैं। ऐसे में बाढ़ आने पर इन गांवों के लोगों को काफी खतरा रहता है। बाढ़ आने पर यहां के पशुओं को भी चारा की कमी हो जाती है। लेकिन, जिला प्रशासन द्वारा इन तीनों प्रखंडों के चिह्नित गांवों में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी कर ली गई है।

लुधियाना में थाना कोतवाली प्रभारी को सूचना आयोग ने किया पांच हजार जुर्माना, आवेदक को समय पर नहीं दी थी जानकारी

लुधियाना । समय पर सूचना नहीं देने और तलब किए जाने पर पेश नहीं होने पर सूचना आयोग ने थाना कोतवाली प्रभारी सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। आयोग ने पुलिस कमिश्नर को जुर्माना थाना प्रभारी के वेतन से काटकर सरकारी खजाने में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा थाना प्रभारी को 12 जुलाई को खुद मांगी गई सूचना के सभी दस्तावेज और रिकार्ड लेकर पेश होने के लिए कहा गया है। मंडी मुलांपुर के रहने वाले जगसीर सिंह ने 18 जून 2020 को सूचना के अधिकार के तहत थाना डिवीजन नंबर एक कोतवाली पुलिस से कुछ जानकारियां मांगी थी। थाना प्रभारी ने एक महीने के अंदर यह जानकारी उन्हें नहीं दी। उन्होंने पुलिस कमिश्नर लुधियाना के पास पहली अपील की। वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। 29 अक्टूबर 2020 को राज्य सूचना आयोग के पास इसकी शिकायत की गई। आयोग ने आठ फरवरी 2021 को थाना प्रभारी को रिकार्ड सहित पेश होने के निर्देश दिए लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद फिर दो बार पेश होने के लिए कहा लेकिन वह फिर भी नहीं पहुंचे। आयोग ने अपने आर्डर में लिखा कि लापरवाही बरतने वाले एसएचओ के खिलाफ 25 हजार रुपये जुर्माना करने का प्रावधान बनता है। फिर भी आयोग उनके प्रति उदारता दिखाते हुए सिर्फ पांच हजार रुपये जुर्माना कर रहा है। जगसीर सिंह का कहना है कि आपराधिक मामलों में 60 से 90 दिन में अदालत में चालान पेश करना होता है। कानून की धारा 167 (2) के तहत अगर समय पर चालान पेश नहीं किया जाए तो आरोपित को बिना कारण जमानत लेने का अधिकार मिल जाता है। कई मामलों में पुलिस आरोपित के साथ मिलीभगत कर चालान समय पर पेश नहीं करती है। ऐसे में पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। वह कई बार लोगों की आवाज उठाने पर जेल गए हैं। उन्होंने वहां देखा कि आरोपित पुलिस से सेटिंग कर चालान में देरी करवाते हैं और आसानी से जमानत पर जेल से बाहर आ जाते हैं। नशा तस्करी के ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है।

उद्योगों पर हेमंत सरकार मेहरबान, बड़े निवेशकों को बड़ी राहत देने की तैयारी; जानें

रांची । हेमंत सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए नीति में कई नए प्रविधानों को जोड़ने की तैयारी में है। सरकार की तैयारियों के अनुसार मध्यम एवं लघु उद्योगों को बड़ी राहत दी जा सकती है। माना जा रहा है कि राज्य में 50 करोड़ रुपये तक का निवेश करनेवाली कंपनियों को 25-30 फीसद तक सब्सिडी देने की घोषणा नई उद्योग प्रोत्साहन नीति में कर सकती है। राज्य सरकार एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सेक्टर को भी बड़ी राहत देने के लिए पूर्व के प्रस्तावों से बड़ा अवसर देने की तैयारी में है।

सरकार की यह भी कोशिश है कि राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जाए और इस बार मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल खोलने पर भी रियायत दी जाएगी। इतना ही नहीं, तैयारियों के अनुसार झारखंड में डिस्टिलरी प्लांट खोलने पर भी सरकार सब्सिडी देगी। दरअसल, पुरानी उद्योग प्रोत्साहन नीति की समय सीमा समाप्त होने के बाद नई उद्योग नीति तैयार करना सरकार के लिए भी जरूरी है। सूत्रों के अनुसार उद्योग विभाग का प्रस्ताव फिलहाल वित्त विभाग के पास है, जहां से कुछ बिंदुओं पर बदलाव की सलाह दी गई है। उद्योग विभाग इस बात को भी ध्यान में रखकर चल रहा है कि नई नीति में उन बातों को नहीं रखा जाए, जिसका लाभ निवेश बढ़ाने में नहीं मिलता। राहत पैकेज बढ़ाने से निवेश बढ़ने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। वित्त विभाग से पास होते ही प्रस्ताव कैबिनेट के पास विचार के लिए पहुंचेगा। ज्ञात हो कि उद्योगों को निवेश के आधार पर राहत कई तरीकों से मिलती है। भवन निर्माण से लेकर बिजली के बिल तक में छूट दी जाती है।नई नीति के इस प्रारूप में पूर्व की नेट, वैट एवं जीएसटी प्रोत्साहन को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। कंपनी के निर्माण लागत, रोजगार के प्रविधान आदि के मानकों के अनुरूप छूट कई फेजों में दी जाती है। इस बार पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त एक प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि इस प्रोत्साहन से राज्य में निवेश को आ रहे औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय राहत मिल सके। कोविड-19 महामारी के बाद औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की मंशा से ये बदलाव किए जा रहे हैं।
उद्योग जगत की मांग पर कई बदलाव- उद्योग नीति में उद्योग जगत की जरूरतों एवं मांग को भी ध्यान में रखा गया है। पुराने और बिना काम के कानूनों और प्रक्रियाओं को समाप्त करने की कवायद भी की जा रही है। सौ से अधिक ऐसे पुराने नियम बदलने की बात की जा रही है, जिसके कारण उद्यमियों को परेशानी होती थी और कहीं ना कहीं निरीक्षण और जांच के नाम पर डराया जाता था। इन नियमों में बदलाव के लिए केंद्र से भी समय-समय पर सुझाव सरकार को मिलते रहे हैं।

सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, 1 लाख युवाओं को जॉब देने की तैयारी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को योगी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश सरकार दिसंबर तक एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही योगी सरकार ने मिशन रोजगार को रफ्तार दे दी है। प्रदेश भर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के साथ राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। जिन विभागों में भर्ती प्रक्रिया कोरोना के कारण रुकी हुई थी वहां युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर चयनित युवाओं की नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए हैं।

कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही प्रदेश भर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के साथ राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पिछले चार साल में अलग अलग विभागों में लगभग चार लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी योगी सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक प्रदेश में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का है। इसके लिए सभी विभागों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिन विभागों में भर्ती प्रक्रिया कोरोना के कारण रुकी हुई थी वहां युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर चयनित युवाओं की नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आबाकारी विभाग में आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नौकरियां मिलने जा रही हैं। योगी सरकार का लक्ष्य साल के अंत तक अपने कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का है।

राज्य सरकार अब तक एक लाख से अधिक महिलाओं की सरकारी नौकरी दे चुकी है, जबकि मनरेगा के जरिये 1.50 करोड़ श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। स्टार्ट अप इकाइयों से पांच लाख और औद्योगिक इकाइयों से तीन लाख से अधिक युवाओं को भी रोजगार दिया जा चुका है। ओडीओपी के माध्यम से 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 50 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों से एक करोड़ 80 लाख लोगों को यूपी में रोजगार मिला है। प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति से पांच लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। 40 लाख से अधिक कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद रोजगार से जोड़ा गया है।

यूपी में अब तक हुई विभागवार भर्ती का ब्योरा = पुलिस विभाग में 137253, बेसिक शिक्षा में 121000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28622, यूपी लोक सेवा आयोग में 27168, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड में 19917, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 8556, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14436, यूपीपीसीएल में 6446, उच्च शिक्षा में 4988, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1112, सहकारिता विभाग में 726, नगर विकास में 700, सिंचाई एवं जल संसाधन में 3309, वित्त विभाग में 614, तकनीकी शिक्षा में 365, कृषि में 2059, आयुष में 1065 लोगों को रोजगार दिए गए हैं। इस प्रकार से कुल 384194 युवाओं को रोजगार मिले हैं। विभिन्न विभागों में 86000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों के 4 लाख स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, इस साल नहीं बढ़ेगी फीस

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्र हित में प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस साल फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बड़े फैसले से एकेटीयू से लगभग 750 इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से संबद्ध निजी क्षेत्र के 1247 डिप्लोमा स्तरीय और 19 अनुदानित संस्थाओ में पढ़ने वाले छात्र छात्रओ को इसका लाभ मिलेगा। सचिव (प्राविधिक शिक्षा) आलोक कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जो फीस पिछले शैक्षिक सत्र 2020-21 में निर्धारित की गई थी, वही इस साल भी ली जाएगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग के इस फैसले से करीब चार लाख विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश के 750 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग-अलग 60 हजार रुपये से लेकर 1.20 लाख रुपये वार्षिक फीस है। वहीं 1,371 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 10 हजार रुपये से लेकर 45 हजार रुपये तक सरकारी व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की फीस निर्धारित है। सभी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पिछले वर्ष तय की गई फीस ही इस सत्र में भी लें। अगर कोई संस्थान इससे अधिक फीस वसूलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिव आलोक कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। प्रदेश में 1247 पॉलिटेक्निक कॉलेज व 750 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 17 अनुदानित संस्थाओं के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। पिछले वर्ष भी कोरोना संक्रमण के कारण फीस वृद्धि पर रोक लगाई थी। इसे चालू शैक्षिक सत्र में भी जारी रखा जाएगा। इस सत्र में फीस 2020-21 के सत्र की ही मान्य होगी।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनेंगे आठ फ्यूल स्टेशन, जमीन के प्रस्ताव भी मंजूर

लखनऊ । जल्द तैयार होने जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आठ फ्यूल स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए आयल मार्केटिंग कंपनियों के चयन के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की 66वीं बोर्ड बैठक में स्वीकृति दे दी गई। इसके साथ ही पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जरूरी जमीन की उपलब्धता के प्रस्ताव भी मंजूर हो गए हैं। यूपीडा बोर्ड की बैठक मंगलवार को मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में विभागीय कार्यालय में हुई। निदेशक मंडल के सदस्य और अन्य अधिकारियों के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना पर आठ फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकारी एवं निजी आयल मार्केटिंग कंपनियों के चयन का प्रस्ताव रखा गया। तय हुआ कि कंपनी ओन्ड कंपनी आपरेटेड पद्धति पर फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए निविदा मूल्यांकन समिति से पहले ही अनुमोदन मिल चुका है। अब उसी आधार कंपनियों का चयन किया जाए। वहीं, मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के सिविल निर्माण की वित्तीय व्यवस्था के लिए एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट फाइनेंशियल एडवाइजरी रिपोर्ट के प्रस्ताव को निदेशक मंडल ने स्वीकृति दे दी। बताया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अब तक कुल 7800 हेक्टेयर के सापेक्ष 4600 हेक्टेयर जमीन की खरीद या अधिग्रहण किया जा चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-दो के तहत आजमगढ़ में रेलवे ओवरब्रिज के अलावा इंटरसेक्शन के लिए भूमि उपलब्ध कराई जानी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अंतिम दौर में चल रहा है। पैकेज-पांच स्थित अम्बेडकर नगर व आजमगढ़ में रेलवे ओवरब्रिज और रैम्प-इंटरचेंज के लिए जमीन दी जानी है।

आगरा में चल रहे कोविड -19 लॉकडाउन में कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के बाद ताजमहल में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक सेल्फी लेते हुए।

बसपा चीफ मायावती ने पार्टी में बगावत से किया इनकार, बोलीं- यह सपा का छलावा, विधायक पहले से ही निलंबित

लखनऊ । बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पार्टी में टूट को नकारते हुए कहा कि घृणित जोड़तोड़, द्वेष व जातिवाद की संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी मीडिया के सहारे यह प्रचारित कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ विधायक टूट कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। मायावती ने इसे घोर छलावा बताते हुए कहा कि इन विधायकों को काफी पहले ही सपा और एक उद्योगपति से मिलीभगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित के बेटे को हराने के आरोप में बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है।

बसपा चीफ मायावती ने बुधवार को लगाता पांच ट्वीट कर सपा को आड़े हाथ लेते हुए कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि सपा अगर इन निलंबित विधायकों के प्रति थोड़ी भी ईमानदार होती तो अब तक इन्हें अधर में नहीं रखती। क्योंकि उनको यह मालूम है कि बीएसपी के यदि इन विधायकों को लिया तो सपा में बगावत व फूट पड़ेगी, जो बीएसपी में आने को आतुर बैठे हैं।

बसपा अध्यक्ष मायावती ने आगे कहा कि जगजाहिर है कि सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है, जिसमें थोड़ा भी सुधार के लिए वह कतई तैयार नहीं हैं। इसी कारण सपा सरकार में बीएसपी सरकार के जनहित के कामों को बंद किया। खासकर भदोई को नया संत रविदास नगर जिला बनाने को भी बदल डाला गया था, जो अति निंदनीय कदम था।

बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने आखिरी ट्वीट में फिर दोहराया कि बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने आदि का मीडिया में प्रचारित करने के लिए मंगलवार को किया गया सपा का नया नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी ज्यादा लगती है। यूपी में बीएसपी जन आकांक्षाओं की पार्टी बनकर उभरी है जो जारी रहेगा।

बता दें कि मंगलवार को बसपा में बगावत से सूबे का सियासी माहौल एकाएक गर्मा गया है। बसपा से निलंबित 11 विधायकों ने एकजुटता दिखाते हुए लालजी वर्मा के नेतृत्व में एक अलग दल बनाने का फैसला कर लिया है। पांच बागी विधायकों ने कल लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। बसपा में कुल 18 विधायकों में से नौ को पार्टी ने निलंबित और दो को निष्काषित कर दिया गया है।

मंगलवार को विक्रमादित्य स्थित सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव से मिलने गए विधायकों की अगुआई श्रावस्ती के विधायक असलम राईनी ने की। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही वे बसपा से हाल ही में निष्कासित किए गए लालजी वर्मा के नेतृत्व में नया दल बनाएंगे। उनके साथ पार्टी के 11 विधायक हैं। अगर ऐसा हुआ तो बसपा का टूटना तय माना जा रहा है।

सोनू सूद की बहन मालविका के पंजाब राजनीति में आने की चर्चाएं तेज

मोगा । फिल्म स्टार एवं कोरोना काल में रियल लाइफ के हीरो बने अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर क्या राजनीति में कदम रखेंगी। मालविका के पंजाब की राजनीति में कदम रखने की चर्चाएं जारों पर है और इस बारे में आज शाम पांच बजे खुलासा हो जाएगा। मालविका की ओर से आज शाम में मीडिया को बुलाया गया है। इसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है।

उनके राजनीति में आने की चर्चा से पहले ही स्थानीय राजनीति में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। अब मालविका सूद सच्चर ने दशहरा ग्राउंड रोड स्थित (एसएस निवास) अपने पैतृक निवास पर बुधवार शाम को अगली रणनीति के खुलासे के लिए मीडिया को आमंत्रित किया है। राजनीति में आने की चर्चा के बीच मालविका सूद के शाम को पांच बजे मीडिया को बुलाने को लेकर एक बार फिर शहर की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है। पिछले साल मार्च महीने में कोरोना काल से पहले जब फिल्म अभिनेता सोनू सूद मोगा में यहां मजदूरों व सरकारी स्कूल में कई किलोमीटर पैदल आने वाला छात्राओं को साइकिलें वितरित कर रहे थे, उसी दौरान फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भी दैनिक जागरण के साथ बात करते हुए खुलासा किया था कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, अभी उन्हें फिल्मी कैरियर में बहुत कुछ करना है। हां अगर मालविका (उनकी छोटी बहन) आना चाहे तो आ सकती है।

अब जबकि साल 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई थीं, करीब ढाई महीने पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब सोनू सूद को वैक्सीनेशन के ब्रांड एंबेसडकर की घोषणा के लिए चंडीगढ़ बुलाया था। उसी दौरान सोनू सूद ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपनी बहन मालविका सूद सच्चर को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात कराई थी। उस मुलाकात के बाद ही शहर में तेजी के साथ चर्चा का दौर शुरू हो गया था।

इन चर्चाओं को बल उस समय मिला जब मालविका सूद सच्चर ने चंडीगढ़ से लौटने के बाद अपनी सक्रियता बढ़ा दी, सोनू सूद को फोकस भी मोगा पर ज्यादा बढ़ गया। वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आन लाइन चर्चा के दौरान भी सोनू सूद ने मालविका सूद सच्चर का नाम मोगा में समाजसेवा के कामों में सक्रिय होने को लेकर तीन बार जिक्र किया था।

गोरखपुर में पूर्व सीएम की बहू पर भाजपा लगा सकती है दांव

गोरखपुर । जलि पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तिर्थि घोषित होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा व समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं में उन नामों की चर्चा फिर से शुरू हो गई, जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव परिणाम आने के बाद मजबूती से अपनी दावेदारी पेश की थी। माना जा रहा है कि भाजपा गोरखपुर में पूर्व मुख्यमंत्री बीर बहादुर सहिं की बहू और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सहिं की पत्नी साधना सहिं पर दांव लगा सकती है। साधना सहिं नर्दिल जलि पंचायत सदस्य हैं।
उलझाने वाला है इस बार का चुनावी गणित- बीते दिनों भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने क्षेत्र की टीम से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित तीन नाम मांगे। पंचायत सदस्य चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन ठीक न होने की वजह से इन नामों के चयन में जिम्मेदारों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। जतिाऊ प्रत्याशी के चयन में उन्हें धन और जन दोनों से शक्तिशाली नाम की तलाश करनी पड़ी। गोरखपुर की बात करें तो यहां 68 वार्डों वाली जिला पंचायत में महज 19 वार्डों में जीत हासिल हो सकी। जीतने वाले छह बागियों को भी भाजपा ने अपने खाते में जोड़ लिया तो भी उसे जीत के लिए 10 और जिला पंचायत सदस्यों की दरकार है। निश्चित तौर पर ऐसे में उस प्रत्याशी पर ही दांव आजमाना होगा, जो इन 10 सीटों को मैनेज कर सके।
ऐसे भारी पड़ा साधना सहिं का नाम
ऐसे में जिन तीन नामों को पार्टी की ओर से भेजे जाने की चर्चा है, उनमें सर्वाधिक चर्चा पहले भी अध्यक्ष की कमान संभाल चुकी साधना सिंह की हैं। उनके पति कैंपियरगंज के विधायक कुंवर फतेह बहादुर सिंह के बारे लोगों का विश्वास है कि वह ही एकमात्र दावेदार हैं, अपने पत्नी के लिए चुनाव का रुख पार्टी के पक्ष में करने में सक्षम हैं। हालांकि दो अन्य दावेदार मायाशंकर शुक्ला और मनोज शुक्ला का भी दावा है कि वह पार्टी के पक्ष में चुनाव का रुख करने में सक्षम हैं लेकिन सूत्रों की मानें तो पार्टी नेतृत्व को ज्यादा भरोसा विधायक के दावे पर ही है। खैर अब वह घड़ी आ गई है, जब किसके दावे पर पार्टी का ज्यादा भरोसा है, वह स्थिति साफ हो जाएगी। इस पद के लिए समाजवादी पार्टी अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। जनवरी 2016 में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में सपा की गीतांजलि यादव ने जीत हासिल की थी।

मुजफ्फरपुर : 12695 नियोजित शिक्षकों के फोल्डर निगरानी को सौंपा

मुजफ्फरपुर । छह वर्ष पूर्व बहाल हुए 13759 नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की मांग निगरानी द्वारा लगातार की जा रही है। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने इनमें 12695 नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों से संबंधित फोल्डर निगरानी को उपलब्ध करा दिया गया है। 13759 में 1064 ऐसे शिक्षक हैं, जो या तो मृत हो गए या बर्खास्त हो गए या वेतन बंद के साथ उनपर कार्रवाई चल रही है। इसकी जानकारी विभाग को भी दे दी गई है। डीपीओ ने बताया कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षक, जिनका प्रमाण पत्र जांच हेतु निगरानी विभाग को सुपुर्द नहीं किया गया था, वे सारे उपलब्ध करा दिए गए हैं। इधर, राजद के प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार ने लोक सूचना अधिकार के तहत पदाधिकारी सह पुलिस निरीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर से डीपीओ द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी शिक्षकों के फोल्डर के बारे जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय को आनलाइन आवेदन किया है।
डीएवी में समर ट्रेनिंग कैंप 18 से- डीएवी खबड़ा में आनलाइन समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं के मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी। 18 से 21 जून तक कार्यक्रम के अंतर्गत पेंङ्क्षटग, म्यूजिक (नृत्य-गायन) चित्रांकन, योग, जीके, नर्सरी राइमस, भाषण कला एवं कुकरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप में जितने भी प्रतिभागी भाग लेंगे उन्हें प्रमाणपत्र दिया जाएगा। लंबे समय से लॉकडाउन के कारण स्कूल से विमुख रहे छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने का यह प्रयास उनमें ऊर्जा स्फूर्ति का नया संचार प्रवाहित करने में सहायक होगा। विस्तृत जानकारी हेतु स्कूल कोर्डिनेटर से संपर्क किया जा सकता है।

रात के अंधेरे में आ रही थी बच्चे के रोने की आवाज, ग्रामीण पास पहुंचे तो कांप गई रुह...

कानपुर । बिल्हौर के ककवन थाना क्षेत्र के फत्तेपुर गांव में एक बच्चे के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई, उसकी हालत जिसने भी देखी वह सहम गया। गांव के बाहर पिटाई के बाद उसे सूनसान इलाके में निर्माणाधीन मकान के पिलर से बांधकर रात के अंधेरे में छोड़ दिया गया। डर की वजह से सारी रात कांपते रहे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो उसकी हालत देखकर उनकी भी रुह कांप गई। अब पुलिस ने बच्चे को अपनी कस्टडी में लेकर उपचार शुरू कराया है, फिलहाल अभी पुलिस को कुछ बताने को तैयार नहीं है।

ककवन थाना क्षेत्र के फत्तेपुर गांव में रहने वाले राम प्रकाश राठौर का 12 वर्षीय पुत्र रमन अपने दोस्त कमल किशोर मंगलवार की शाम गांव के पास पेड़ से जामुन तोड़कर खा रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार इस दौरान रमन ने जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारा, जो कमल किशोर के सिर में लग गया। पत्थर लगने से कमल किशोर जख्मी हो गया, इसकी जानकारी पर स्वजन पहुंच गए और उसे अस्पताल ले गए।
खून का बदला खूने से- कमल किशोर के जख्मी होने से नाराज पिता राजू ने राम प्रकाश के घर पर जाकर गाली गलौज की और खून का बदला खून से लेने की बात कही। आरोप है कि देर रात राजू ने रमन को पकड़ने के बाद मारपीट की। इसके बाद उसे गांव से 100 मीटर दूर सड़क किनारे सूनसान इलाके में निर्माणाधीन मकान के अंदर ले गया। राजू ने रमन को रात के अंधेरे में मकान के पिलर में बांध दिया और वहां से चला गया। रात के अंधेरे में रमन डर से कांपता रहा।
आधी रात रास्ते से गुजरे ग्रामीणों को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो ग्रामीणों के कदम ठिठक गए। आवाज की दिशा में ग्रामीण पहुंचे तो नजारा देखकर उनकी भी रुह कांप गई। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रमन को बंधन मुक्त किया। थाना प्रभारी संतोष कुमार ओझा ने बताया की अभी बच्चा अभी बहुत सहमा हुआ है और कुछ सही बता नहीं पा रहा है। पूछताछ की जा रही है, तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कोलकाता में फ्री मेगा वैक्सीनेशन कैंप के दौरान लाभार्थी कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक प्राप्त करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए।

गुवाहाटी में असम राज्य चिड़ियाघर सह बॉटनिकल गार्डन में एक जूकीपर 15 महीने के हाथी के बछड़े को खाना खिलाते हुए।

पुडुचेरी में विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने भाजपा विधायक इमबलम आर सेल्वम का अभिनंदन करते हुए।

एक नजर

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली, यूपी, मुंबई के बीच चलने जा रही ये स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली । कोरोना महामारी की दूसरी रफ्तार धीमी होने के साथ ही भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है। यात्रियों की सुविधा और यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए रेलवे ने कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को बहाल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत उत्तर मध्य रेलवे ने तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। गाड़ी संख्या 04137 प्रयागराज-आनंदविहार सुपरफास्ट हमसफर स्पेशल एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन चलेगी। यह ट्रेन 23 जून से शुरू होगी और प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को अगले निर्देश तक चलेगी। प्रयागराज से यह गाड़ी 22:30 बजे रवाना होगी और 06:05 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 04138 आनंद विहार- प्रयागराज स्पेशल 24 जून से प्रत्येक मंगलवार, गुरूवार और रविवार को चलेगी। आनंद विहार से यह गाड़ी 22:35 बजे रवाना होगी और 6:20 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यह गाड़ी सिर्फ कानपुर सेंट्रल पर ही रूकेगी। ट्रेन नंबर 05401 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक पूर्ण आरक्षित ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से 6 जून, 23 जून, 30 जून और 7 जुलाई को चलेगी। गोरखपुर से यह ट्रेन 19:00 बजे पर रवाना होगी और 05:00 बजे लोकमान्य तिलक स्टेशन पहुंचेगी। वहीं, लोकमान्य तिलक से यह ट्रेन (ट्रेन नंबर 05402)18 जून, 25 जून, 2 जुलाई और 9 जुलाई को 07:50 बजे चलेगी और 16:15 बजे गोरखपुर पहुंच जाएगी। यह गाड़ी कानपुर सेंट्रल, भरवा सुमेरपुर, रागौल, बांदा और चित्रकूट स्ट्शनों पर रूकेगी। गांड़ी संख्या 05403 गोरखपिुर-बांद्रा ग्रषमकालीन स्पेशल ट्रेन 18 जून को गोरखपुर से 05:00 बजे रवाना होगी और 14:25 बजे बांद्रा स्टेशन पर पहुंचेगी। वहीं, 19 जून को यह ट्रेन (05404) बांद्रा से 19:25 बजे चलेगी और 6:45 बजे गोरखपुर पहुंच जाएगी। यह गाड़ी कानपुर सेंट्रल, मथुरा जंक्शन, अछनेरा जंक्शन और भरतपुर में रूकेगी।

गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के मुद्दे पर दो हफ्ते बाद सुनवाई, सीएए कनेक्शन से केंद्र का इनकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आइयूएमएल) की उस याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाने संबंधी केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी गई है।जस्टिर हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र ने इस मामले पर सोमवार को जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। इसका उत्तर देने के लिए उन्हें दो हफ्ते का समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह दो सप्ताह बाद मामले की सुनवाई करेगा।

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसकी अधिसूचना संशोधित नागरिकता कानून, 2019 (सीएए) से संबंधित नहीं है। यह (अधिसूचना) केंद्र सरकार के पास निहित शक्ति स्थानीय अधिकारियों को सौंपने की प्रकिया मात्र है।गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2004, 2005, 206, 2016 और 2018 में भी इसी तरह का अधिकार दिया था और विभिन्न विदेशी नागरिकों के बीच उस पात्रता मानदंड के संबंध में कोई छूट नहीं दी गई है जो नागरिकता कानून 1955 और उसके तहत बनाए गए नियमों में तय किए गए हैं। क्या है मामला - आइयूएमएल ने एक जून को न्यायालय में केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी थी। याचिका में दलील दी गई थी कि केंद्र सीएए के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली आइयूएमएल द्वारा दायर लंबित याचिका में न्यायालय को दिए गए आश्वासन को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। केंद्र ने आश्वासन दिया था कि सीएए के नियम अभी तय नहीं हुए हैं इसलिए उस पर स्थगन लगाना जरूरी नहीं है।

सीएए में क्या है - सीएए में 31 दिसंबर, 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ना सहने की वजह से भारत आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इन अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं।

लॉकडाउन से परेशान हाथी पालकों को मदद करेगी राजस्थान सरकार

जयपुर । कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप्प होने का असर हाथी पालकों को भी हो रहा है। जयपुर में हाथी की सवारी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय रहती है। पिछले कुछ समय से हाथी की सवारी बंद होने के कारण इनके पालकों व महावतों की गंभीर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने हाथियों के भरण-पोषण के लिए 1500 रूपए प्रतिदिन की दर से पालकों को देने का निर्णय लिया गया है। यह सहायता राशि 17 अप्रैल से 31 मई, 2021 की अवधि के लिए ही देय होगी।

यह आर्थिक मदद मुख्यमंत्री सहायता कोष से की गई है। सभी हाथी पालकों के लिए यह रकम हाथी कल्याण संस्थान के खाते में हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि पिछले साल भी कोरोना के दौरान हाथी पालक परिवारों के समक्ष उत्पन्न हुए आर्थिक संकट को देखते हुए मार्च से लेकर दिसंबर, 2020 की अवधि के लिए हाथी कल्याण संस्थान को 4.21 करोड़ की सहायता राशि आवंटित की गई थी। गहलोत ने कहा, लॉकडाउन और पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण हाथी पालकों की आजीविका प्रभावित होने के कारण सरकार ने आर्थिक मदद करने का निर्णय लिया है। इस मदद से हाथी पालक परिवारों को संबल मिलेगा। उल्लेखनीय है कि जयपुर में हाथी गांव बसा हुआ हैं। यहां रह रहे महावतों के पास कुल 103 हाथी हैं । ये हाथी पर्यटकों में आमेर महल की सवारी कराने के साथ ही शादियों में काम आते हैं।

गुजरात में कोरोना संक्रमण के 352 नए मरीज, 4 की मौत

अहमदाबाद । गुजरात में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 8 लाख 21 हजार 078 गई है। वही कोरोना से मरने वालों की संख्या 10007 हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 352 केस दर्ज किए गए जबकि 4 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 8884 है जबकि अब तक 8 लाख 21 हजार 078 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं।

अहमदाबाद महानगर पालिका में कोरोना से दो की मौत दर्ज की गई है जबकि सूरत तथा जूनागढ़ जिले में 1-1 की मौत हुई है। 3 जिलों के अलावा किसी भी जिले अथवा शहर में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। अहमदाबाद महानगर पालिका में 48 केस दर्ज किए गए जबकि मरने वालों की संख्या 2 रही।

इस तकनीक से फिर से इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं एन95 मास्क और पीपीई

नई दिल्ली । मौजूदा समय में मास्क और पीपीई किट की मांग सबसे अधिक है। मुंबई के एक स्टार्टअप ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके द्वारा पीपीई किट और मास्क का इस्तेमाल फिर से किया जा सकता है। इस तकनीक का प्रयोग महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के कई अस्पतालों में किया जा रहा है। मास्क और पीपीई किट का फिर से इस्तेमाल होने से एक तरफ जहां कोविड-19 जैव अपशिष्ट को कम करने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही इससे पर्यावरण को भी दुरुस्त रखने में सहायता मिलती है।

इस प्रणाली को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई (मुम्बई) के जैवविज्ञान एवं जैव अभियांत्रिकी विभाग में परीक्षण के बाद सत्यापित किया जा चुका है और इसे विषाणुओं और जीवाणुओं को निष्क्रिय करने में 5 एलओजी (99.999 प्रतिशत) से अधिक प्रभावपूर्ण पाया गया है। इसे सीएसआईआर -एनईईआरआई से भी स्वीकृति मिल चुकी है और यह आईपी55 प्रमाणित भी है।

इस प्रणाली को स्टार्ट-अप इंद्र वाटर ने बनाया है। इसके लिए स्टार्टअप को एसआईएनई- आईआईटी बम्बई के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से अनुदान मिला था। एसआईएनई-आईआईटी बम्बई की सहायता से इस स्टार्टअप ने हर महीने 25 विसंक्रमण प्रणालियाँ बनाकर उनकी आपूर्ति करने के लिए अपने आप को तैयार किया।

ये हैं वज्र कवच

इस उत्पाद में एक बहुचरणीय विसंक्रमण प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिसके अंतर्गत पीपीई किट में कोरोना संक्रमण से निकले विषाक्त तत्वों, विषाणु (वायरस), जीवाणु (बैक्टीरिया) को यूवी-सी प्रकाश स्पेक्ट्रम के माध्यम से 99.99 प्रतिशत प्रभावशीलता तक निष्क्रिय किया जा सकता है। वज्र कवच नाम की विसंक्रमण (डिसइंफेक्शन) प्रणाली की मदद से पीपीई किट,मास्क को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे महामारी से लड़ने की लागत को काफी कम करने और अत्यधिक मात्रा में बनने वाले कोविड-19 जैव अपशिष्ट को कम करने में सहायता मिलती है। इससे पर्यावरण ठीक रखने में भी सहायता मिलती है। यह प्रणाली व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को उचित एवं तर्कसंगत मूल्यों पर अधिक मात्रा में सबके लिए उपलब्ध भी करवाती है।

क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए पीआरआई कर रहा मदद- पीआरआई ने क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण 'कोविड सपोर्ट' के तहत दिए हैं। अस्पतालों को 100 वेंटिलेटर, 105 हाई फ्लो नोजल कैनुलास (एचएफएनसी), 35 मल्टीपैरा मॉनिटर दिए गए हैं। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर हेल्थ केयर वर्कर्स और लोगों के व्यक्तिगत यूज के लिए प्रदान किए गए हैं। यह सामग्री 17 राज्यों में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए खासकर दी गई। इनमें इंडियन नेवी, पंजाब पुलिस, एयर फोर्स और राज्यों के स्वास्थ्य विभाग भी शामिल हैं। कंपनी ऑक्सीजन सिस्टम (पीएसए) सेटअप करने में भी कई जगह मदद कर रही है। इनमें 5 अस्पताल उत्तर प्रदेश के, रोहतक का पीजीआई, महाराष्ट्र में नासिक का एक यूनिट और एक स्थान पर फ्रांस सरकार के जरिए यह सिस्टम डोनेट किया गया है। कई जगह आइसोलेशन वार्ड बनाने में मदद की गई है। 350 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर दिए गए हैं। चौदह मोबाइल कोविड हेल्प वैन और चार एंबुलेंस प्रदान करने से दो लाख 81 हजार से ज्यादा लोगों को मदद मिली है।

क्या कोवैक्सीन में है नवजात बछड़े का सीरम, केंद्र सरकार ने कहा- तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए तथ्य

नई दिल्ली । भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में बहुत से भ्रम आज तक हैं। ये भ्रम आमतौर पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैलाए जाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस रोधी टीके कोवैक्सीन को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इससे इन्कार किया है।

इस बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस रोधी टीके कोवैक्सीन की कॉम्पज़िशन (संरचना) के संबंध में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इस वायरल पोस्ट में यह कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन के कॉम्पज़िशन में नवजात बछड़े का सीरम मिलाया गया है। इस पोस्ट में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।

मंत्रालय की ओर से बताया गया कि नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग केवल वेरो कोशिकाओं की तैयारी और वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोजातीय और अन्य जानवरों से प्राप्त सीरम मानक संवर्धन घटक हैं, जिनका उपयोग विश्व स्तर पर वेरो सेल के विकास के लिए किया जाता है। वेरो कोशिकाओं का उपयोग कोशिका जीवन को स्थापित करने के लिए किया जाता है, जो टीकों के उत्पादन में मदद करते हैं। पोलियो, रेबीज और इन्फ्लूएंजा के टीके विकसित करने में इस तकनीक का उपयोग दशकों से किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि वीरो सेल्स के विकास के बाद उन्हें कई बार पानी एवं केमिकल से साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया में वीरो सेल्स से बछड़े के सीरम दूर हो जाता है। इसके बाद वायरल ग्रोथ के लिए वीरो सेल्स को कोरोना वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है। वायरल ग्रोथ के दौरान वीरो सेल्स पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न वायरस नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद मरे हुए वायरस का इस्तेमाल फाइनल वैक्सीन बनाने में किया जाता है।

मंत्रालय ने साफ किया कि अंतिम टीके की सामग्री में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं होता है। सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चा हो रही है कि कोरोना टीकों के निर्माण में गोवंश या जानवरों के सीरम का इस्तेमाल हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं होता है।

विशाखापत्तनम में पुलिस के साथ मुठभेड़ में छह नक्सली मारे गए, मौके से हथियार भी बरामद

विशाखापत्तनम, एजेंसियां । आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के कोय्यूरु गांव में आज सुबह नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें छह नक्सली मारे गए हैं। इनमें इनका एक वरिष्ठ नेता और एक महिला सदस्य भी शामिल हैं।फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके से हथियार भी बरामद हुए हैं। ये नक्सली प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के सदस्य थे। आंध्र प्रदेश पुलिस ने इसकी जानकारी दी है।

डीजीपी कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मम्पा थाना क्षेत्र के तीगलामेट्टा वन क्षेत्र में सुबह के समय भाकपा (माओवादी) और राज्य के नक्सल विरोधी बल ग्रेहाउंड्स के बीच मुठभेड़ हो गई। प्राथमित जानकारी के अनुसार छह शव बरामद किए गए हैं। मौके से एक एके-47, एक एसएलआर, एक कार्बाइन, तीन .303 राइफल और एक तमंचा (देशी पिस्तौल) बरामद किया गया है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है और इसे लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

नक्सलियों को करीब 10 लाख रुपये नकद देने जाते हुए तीन गिरफ्तार

बता दें कि इस तेलंगाना पुलिस ने पूर्वी गोदावरी जिले में 14 जून को नक्सलियों को करीब 10 लाख रुपये नकद देने जाते हुए तीन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा था। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए चिंतूर के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), कादर बाशा ने बताया कि नक्सलियों ने बीड़ी ठेकेदारों से उक्त पैसे वसूल करने की योजना बनाई थी।

दो बाइक पर तीन व्यक्ति आए, पुलिस को देखकर भागने लगे

उन्होंने बताया कि सोमवार शाम को, पूर्वी गोदावरी जिले के एसपी ने विश्वसनीय जानकारी के आधार पर पुलिस को गोरलागुडेम जंक्शन पर वाहनों की जांच करने का आदेश दिया। शाम लगभग 4 बजे, चिंतूर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने मौके पर जाकर वाहनों का निरीक्षण किया। उस समय कुनावरम की ओर से दो बाइक पर तीन व्यक्ति आए। उन्होंने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में लिया और जांच में उनके पास से 9,93,000 रुपये नकद बरामद हुए।

अशोक गहलोत का आलाकमान को संदेश- फिलहाल नहीं करेंगे वन टू वन मुलाकात, दिल्ली आना भी संभव नहीं

जयपुर । राजस्थान में कांग्रेस की गतिविधियां बुधवार को तेज रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे अपनी-अपनी रणनीति बनाते रहे। इसी बीच सीएम गहलोत ने नया दांव चलते हुए पायलट खेमे को बैकफुट पर लाने वाला माना जा रहा है। गहलोत ने एक तरफ तो जहां पायलट के साथ खींचतान में खुद को पर्दे के पीछे रखकर कई तरह की चाल चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों की लगाम कसने के लिहाज से मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रशासनिक सुधार विभाग से मंत्रिपरिषद के सदस्यों का रिपोर्ट कॉर्ड मांगा है।

रिपोर्ट कार्ड मांगकर गहलोत ने मंत्रियों में संभावित फेरबदल का संदेश दिया कि उन्हे सीएम खेमे में ही रहना है। बुधवार को मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया। पायलट के साथ चल रही सियासी खींचतान के बीच सीएम ने चिकित्सकों की सलाह के नाम पर खुद को लंबे समय तक क्वारंटीन कर लिया है। जिस तरह से आलाकमान और पायलट खेमा पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दबाव बना रहे थे, उसको देखते हुए गहलोत ने साफ संकेत दे दिया कि वे किसी दबाव में नहीं आएंगे।

आलाकमान के कहने पर भी वे दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। लंबे क्वारंटीन का मतलब है कि गहलोत पायलट और आलाकमान को ज्यादा तूल नहीं देते हुए बेफिक्री दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ संकेत दिया कि वे ना तो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और ना ही विवाद निपटाने के लिए व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सीएम से बात कर बीच का रास्ता निकालने का आग्रह किया,लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि पोस्ट कोविड की बीमारियों से बचने के लिए चिकित्सकों की सलाह पर वे फिलहाल वन टू वन मुलाकात नहीं कर सकते।

गहलोत को बताया कलयुग का भगवान

इसी बीच पायलट के विश्वस्त विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने गहलोत को कलयुग का भगवान बताते हुए कहा कि जिस तरह अपनी मन्नत पूरी करने को लेकर लोग मंदिर में जाते हैं। वैसे ही हम बार-बार गहलोत से मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर रहे हैं। वे मौजूदा समय में भगवान हो रहे हैं।

दो दिन पहले सीएम की तारीफ करने वाले विधायक इंद्रराज गुर्जर ने फिर पाला बदला और एक बयान में कहा कि पायलट कांग्रेस की ब्राण्ड बन गए हैं।

हर दिन चल रही नई चाल- आलाकमान और पायलट खेमे के दबाव से निपटपने के लिए सीएम हर दिन नई चाल चल रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने पायलट खेमा छोड़कर आए 7वीं बार विधायक बने भंवरलाल शर्मा को मैदान में उतारकर कहलवाया कि पायलट को गहलोत को नेता मानना पड़ेगा। बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों से पायलट खेमे को गद्दार कहलवा दिया। हालांकि पायलट खेमे के दो विधायकों ने इसका जवाब दिया और कहा कि जो लोग पार्टी बदलते हैं वे हम पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने ढ़ाई साल में तीन पार्टी बदली है। सूत्रों के अनुसार बुधवार को सीएम की कई विधायकों से वर्चुअल बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने एकजुट रहने की सलाह दी।

पांच साल की बच्ची ने बचाई अपनी मां की जान, समय रहते 100 नंबर पर कर दिया था फोन

उदयपुर । अंबामाता थाना क्षेत्र में पांच साल की एक बालिका ने अपनी मां की जान बचा ली। समय रहते पुलिस उनके घर पहुंची हैरान रह गई कि विवाहिता की हत्या का प्रयास किया गया और यह काम उसके पति और सास ने किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया, जबकि पीड़िता को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पता चला कि गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास ही नहीं किया गया, बल्कि जहर देकर उसकी जान लेने की भी कोशिश की गई।

मिली जानकारी के अनुसार घटना शहर के अंबामाता क्षेत्र की है। जहां अमरनगर से एक बालिका का फोन पुलिस को आया था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि निशा संवारिया घायल अवस्था में मिली। जिसके साथ उसके पति नरेंद्र और सास शांता सांवरिया ने मारपीट की। महिला के बेहोश होने पर उसे तत्काल क्षेत्र के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उसे जहर दिया गया। उपचार के बाद जब महिला को होश आया तो पता चला कि उसे जहर और किसी ने नहीं, बल्कि उसके पति और सास ने मिलकर दिया। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज करने के बाद हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया।

थानाधिकारी सुनील टेलर का कहना है कि मां निशा के कहने पर उसकी पांच साल की बेटी दिशा ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर दिया था। जिससे उसे बचाया जा सका। मामले की जांच की जा रही है और लगाए गए आरोप साबित होने पर आरोपी पति नरेंद्र और सास शांता सांवरिया की गिरफ्तारी की जाएगी।

इधर, पीड़िता के भाई अंबामाता यादव कॉलोनी निवासी अंबालाल खटीक ने बताया कि उसकी बहन निशा की शादी नरेंद्र सांवरिया से सात साल पहले हुई थी और उसकी पांच साल की भांजी है। शादी के कुछ महीने बाद उनका बहनोई नरेंद्र ने बहन निशा के साथ मारपीट शुरू कर दी। जिस पर उसने महिला थाने में मामला दर्ज कराया था। हालांकि परिवार और समाज के दबाव के बाद इस मामले में उनके बीच राजीनामा हो गया था।

गला घोंटकर कोरोना संक्रमित की हत्या, अस्पताल कर्मचारी ने बताई जुर्म के पीछे की वजह

चेन्नई । तमिलनाडु में एक कोरोना के मरीज की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। यहां एक सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही महिला कर्मचारी ने एक कोरोना के मरीज की गला घोंटकर हत्या कर दी है। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि उसे पैसों और सेलफोन की जरूरत थी, जिस वजह से उसने यह मर्डर किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि मृतक को 23 मई को कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था और आठ जून को उसका शव मिला।

बताया गया कि मृतक करीब दो हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थी। संक्रमित को 23 मई को कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था और आठ जून को उसका शव मिला।

गुजरात में लागू हुआ लव जिहाद कानून, संशोधन कर और बनाया सख्त

अहमदाबाद । गुजरात में बुधवार से धर्म स्वतंत्रता सुधार कानून लागू हो गया है। प्रदेश में अब किसी भी तरह से छल, बल, लालच अथवा बहला फुसलाकर कर किसी युवती से विवाह कर उसका धर्म परिवर्तन कराना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 5 साल तक की सजा हो सकती है वहीं इसमें मदद करने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। युवती नाबालिग होने अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय से होने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गुजरात सरकार ने पिछले मानसून सत्र में गुजरात धर्म स्वतंत्रता सुधार अधिनियम 2021 पारित किया था जिसे राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पिछले महीने अपनी मंजूरी दे दी थी। राज्यपाल ने लव जिहाद कानून सहित अब तक इस सरकार के करीब 15 कानूनों को अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। गुजरात सरकार ने युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए विवाह करने अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने को अवैध बना दिया है। इस तरह छल बल अथवा प्रभाव में लेकर बहला-फुसलाकर किसी युवती से विवाह कर उसके धर्म का परिवर्तन कराने वाले को 5 साल तक की सजा हो सकती जबकि लड़की नाबालिग होने अथवा एससी एसटी वर्ग से होने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस तरह के विवाह की शिकायत माता-पिता रक्त संबंधी अथवा पीड़िता के परिवार का कोई भी सदस्य अथवा रिश्तेदार शिकायत कर सकेगा। विवाह में मदद करने वाले व्यक्ति तथा संस्थाओं को भी इस कानून के तहत दोषी माना जाएगा तथा विवाह कराने वाली संस्था के पदाधिकारी को 10 साल तक की भी सजा हो सकती है।

सरकार ने लव जिहाद कानून को बहुत सख्त बनाते हुए धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। धर्म परिवर्तन के लिए किसी युवती से विवाह करना तथा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन दोनों को ही अपराध माना जाएगा। लव जिहाद कानून अब गुजरात धर्म स्वतंत्रता सुधार अधिनियम 2021 के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधायक 2003 अस्तित्व में था लेकिन सरकार ने इस कानून में संशोधन कर इसे और भी सख्त बना दिया है जिससे धर्म परिवर्तन कराना अब बहुत मुश्किल होगा।

अनन्या पांडे

को इन PHOTOS के कैप्शन लेकर है बड़ी उलझन, क्या आप करेंगे मदद?

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Pandey) हमेशा अपनी क्यूटनेस से लोगों का दिल जीतती हैं. लेकिन इस बार वह अपनी PHOTOS को शेयर करते वक्त एक दुविधा में हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के लिए कैप्शन खत्म हो गए हैं.

मिरर सेल्फी में दिखा स्वैग

अनन्या ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों का एक सेट पोस्ट किया. तस्वीरों में एक्ट्रेस मिरर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं. एक्टर चंकी पांडे की बेटी न्यूड मेकअप और पिंक लिप स्टेन के साथ ब्लैक आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

कैप्शन को लेकर है परेशानी

कैप्शन के लिए अनन्या ने लिखा, (दिल और आग इमोजी) (आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि मैं सचमुच अब कैप्शन के बारे में नहीं सोच पा रही हूं लेकिन मैं वापस आ आऊंगी).

करने जा रही हैं तेलुगु डेब्यू

एक्ट्रेस अगली बार तेलुगु स्टार विजय देवरकोंडा के साथ फिल्म 'लिगर' में दिखाई देंगी. फिल्म का निर्देशन पुरी जगन्नाथ ने किया है. करण जौहर द्वारा निर्मित यह फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है. इसके साथ ही वह दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ शकुन बत्रा की अगली फिल्म में भी अभिनय करेंगी.

सोनू सूद की राजनीति में होगी ऐसी एंट्री? कहा- छत पर चढ़कर करूंगा ऐलान

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) की फैन फॉलोइंग खूब है. लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं. वे जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है. सोनू इस सब से भागते नहीं बल्कि हर चाहनेवाले से मुलाकात करते हैं. उनकी दरियादिली को देख लोग बार-बार उनसे एक सवाल जरूर करते हैं कि क्या वो राजनीति में पैर जमाने वाले हैं? अब तक लो सोनू सूद इस पर न ही कहते रहे हैं, लेकिन इस बार सोनू सूद ने अलग ही जवाब दिया है.

अभी नहीं हूं तैयार

ईटीवी भारत को दिए एक इंटरव्यू में सोनू सूद (Sonu Sood) ने कुछ ऐसा कहा, जिससे अब फैंस को लगने लगा है कि आज नहीं तो कल सोनू राजनीति में आएंगे. वहीं कई लोग मान रहे हैं कि सोनू समाज सेवा कर अभी से राजनीति में अपने पैर जमाने की तैयारी कर चुके हैं. सोनू सूद ने इस मामले पर कहा, राजनीति कमाल का क्षेत्र है. अफसोस है कि लोगोंन ने इसे रंग दे दिया है. मैं राजनीति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक्टर के तौर पर बहुत कुछ अभी भी करना बाकी है.

छत पर चढ़कर करेंगे ऐलान

सोनू सूद (Sonu Sood) ने इस बातचीत में आगे कहा, 'मैं अपने हाईवे खुद बनाता हूं. मैंने कभी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया. मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं. मैं अब भी लोगों की मदद कर रहा हूं. राजनेता बनने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, मुझे जब ये लगने लगेगा कि मैं तैयार हूं तो रूफ टॉप पर चढ़कर कहूंगा कि हां मैं तैयार हूं राजनीति में आने के लिए.

फैंस हैं सोनू के दीवाने

वैसे इस बयान से तो यही लग रहा है कि सोनू (Sonu Sood) ने अपना रुझान राजनीति की ओर थोड़ा बढ़ाया है और हो सकता है कि वो जल्द राजनीति करने उतरे. पहले भी कई बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के सितारें राजनीति में कदम रख चुके हैं और सफल भी रहे हैं. अब ये देखने वाली बात होगी कि सोनू सूद पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं या नहीं. वैसे उन्हें फैंस बहुत प्यार करते हैं. बीते दिनों ही उनका एक फैन बिना चप्पल के उनसे मिलने मुंबई पहुंचा था. इससे पहले उनकी तस्वीर को दूध से नहलाने का वीडियो भी वायरल हुआ था.

सुशांत सिंह राजपूत की पहली डेथ एनिवर्सरी पर अंकिता लोखंडे ने रखा है हवन, शेयर किया वीडियो

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पहली डेथ एनिवर्सरी पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है. एक्टर को इस दुनिया से गए आज पूरा एक साल हो गया है. टीवी शो पवित्र रिश्ता (Pavitra Rishta) में सुशांत के साथ काम कर चुकीं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने आज के दिन अपने घर पर हवन रखा है. उन्होंने इसका वीडिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है.

शेयर की हवन कुंड की वीडियो

अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर ये क्लिप शेयर की है जिसमें हवन कुंड में जलती आग नजर आ रही है. मालूम हो कि पवित्र रिश्ता (Pavitra Rishta) के सेट पर ही सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) और अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) की मुलाकात हुई थी. वक्त के साथ दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फिर धीरे-धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल गई.

खत्म हो गया अंकिता-सुशांत का रिश्ता

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने एक रियलिटी टीवी शो पर अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) को शादी के लिए प्रपोज भी किया था जिसके जवाब में अंकिता ने एक्टर को हां कहा था. हालांकि जहां सुशांत के करियर ने रफ्तार पकड़ ली थी वहीं अंकिता की गाड़ी अब भी शुरुआती गियर्स में ही थी. लिहाजा दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और दोनों ने एक समय के बाद अपने रास्ते अलग कर लिए.

सोशल मीडिया से लिया था ब्रेक

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की डेथ एनिवर्सरी से थोड़ा ही पहले एक्ट्रेस ने अनाउंस किया था कि वह कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं. हालांकि उनका सुशांत की पहली डेथ एनिवर्सरी से पहले ऐसा करना फैंस को रास नहीं आया और उनके इस सोशल मीडिया डिटॉक्स की अनाउंसमेंट पर लोगों ने अंकिता को जमकर ट्रोल किया था.

पहली पत्नी को लेकर पति राज कुंद्रा के खुलासे से परेशान हुईं

शिल्पा शेट्टी

शेयर की इमोशनल पोस्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) इन दिनों काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं. हाल ही में राज ने अपनी एक्स वाइफ कविता (Kavita Kundra) को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

राज का खुलासा

राज कुंद्रा ने हाल ही में इंटरव्यू में साफ किया कि उनकी पहली शादी टूटने का कारण कभी भी शिल्पा नहीं थीं. राज ने बताया कि उनकी पूर्व पत्नी ने उन्हें धोखा दिया था, कविता का उनकी बहन के एक्स हस्बैंड के साथ अफेयर था जिस वजह से यह शादी टूटी.

शिल्पा ने शेयर की स्टोरी

इसी बीच शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) का एक पोस्ट सुर्खियों में है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक बुक की फोटो शेयर की है. जिसमें शेयर्ड सफरिंग्स वाला पन्ना नजर आ रहा है. जिसमें लिखा है, अच्छाई अलगाव में मौजूद नहीं है. अच्छाई का प्रत्येक कार्य अधिक अच्छे में योगदान देता है. इसी तरह जब हम कोई अच्छा काम करने में देरी करते हैं तो हम सभी को भुगतना पड़ता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट

इसमें आगे लिखा है, %कभी-कभी हम अच्छे लोगों के साथ किए जा रहे बुरे कार्यों के बारे में देखते या सुनते हैं और हम कुछ नहीं करते क्योंकि वो हमसे बहुत दूर या कटी हुई लगती हैं. दुनिया में कहीं भी जब एक अच्छे व्यक्ति पर हमला किया जाता है, घायल किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है या मार दिया जाता है तो हम सब थोड़े असुरक्षित हो जाते हैं.% शिल्पा का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कयास लगा रहे हैं कि उनका इशारा पति राज द्वारा किएग ए खुलासे की ओर है.

शादी टूटने में शिल्पा का नहीं था हाथ

आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) पर राज कुंद्रा (Raj Kundra) की पहली पत्नी कविता कुंद्रा (Kavita Kundra) ने उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया था, लेकिन राज ने साफ किया कि इसमें शिल्पा का कोई हाथ नहीं है. दोनों उस समय एक-दूसरे को जानते भी नहीं थे. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने साल 2009 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) संग शादी रचाई थी. शिल्पा से राज की यह दूसरी शादी थी.

तीन साल चली थी पहली शादी

इससे पहले राज कुंद्रा ने साल 2003 में मॉडल कविता कुंद्रा (Kavita Kundra) संग शादी के बंधन में बंधे थे लेकिन दोनों की शादी महज 3 साल तक ही चली और साल 2006 में दोनों का तलाक हो गया. तलाक के बाद राज और शिल्पा करीब आए और दोनों ने 22 नवंबर 2009 को सात फेरे लिए.

इसी बीच दोनों की शादी के बाद राज की एक्स वाइफ कविता ने मीडिया के सामने आकर शिल्पा पर कई तरह के आरोप लगाए और साथ ही यह भी कहा कि शिल्पा की वजह से उनकी शादी टूटी.

हाले में जर्मनी के एलेकजेंडर ज्वरेव एटीपी टेनिस मुकाबले में रिटर्न शॉट लगाते हुए।

स्पॉट फिक्सिंग में फंसे स्पिनर अंकित चव्हाण का प्रतिबंध समाप्त

मुम्बई, (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने स्पॉट फिक्सिंग में फंसे स्पिनर अंकित चव्हाण का प्रतिबंध समाप्त कर दिया है। अब अंकित पेशेवर क्रिकेट खेल सकेगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने प्रतिबंध समाप्त किये जाने को सही करार दिया। साथ ही कहा कि अब यह स्पिनर पेशेवर क्रिकेट खेल सकेगा। इससे पहले साल 2013 में इस खिलाड़ी को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के छठे संस्करण के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसे दिल्ली पुलिस ने अन्य दो क्रिकेटरों अजीत चंदीला और श्रीसंत के साथ गिरफ्तार किया था। ये तीनों तब राजस्थान रॉयल्स की टीम में थे। इस मामले में सितंबर 2013 में चव्हाण और श्रीसंत को बीसीसीआई की अनुशासन समिति द्वारा क्रिकेट से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया था हालांकि, जुलाई 2015 में दिल्ली की एक अदालत ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में इन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। वहीं श्रीसंत का प्रतिबंध पिछले साल ही समाप्त हो गया था। इसके बाद से ही वह घरेलू क्रिकेट खेलने लगे हैं।

आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय टीम घोषित

साउथम्पटन, (एजेंसी)। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जून से होने वाले आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। भारतीय प्रबंधन ने टीम घोषित किये जाने के अलावा न्यूजीलैंड टीम पर बायो बबल के नियमों को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। आईसीसी ने न्यूजीलैंड की टीम के 6 सदस्यों को करीब के एक गोल्फ कोर्स में जाने की अनुमति दे दी गई जिसपर भारतीय पक्ष ने आपत्ति जतायी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, हेनरी निकोल्स, मिशेल सेंटनर, डेरिल मिशेल और फिजियो टॉय सिमसेक गोल्फ कोर्स गए थे। यह गोल्फ कोर्स एजिस बॉल के परिसर में ही स्थित है लेकिन भारतीय टीम का कहना है कि नियम दोनों टीमों के लिए एक समान होने चाहिए। एक भारतीय टीम सदस्य ने कहा, खिलाड़ियों और उनके परिवारों से कहा गया है कि वे होटल में अपने सम्बंधित फ्लोर से बाहर न निकलें जब तक मैदान में न जाना हो लेकिन आज सुबह हमें पता चला कि 6 कीवी खिलाड़ी गोल्फ कोर्स में खेलने गए थे।

वहीं दूसरी ओर आईसीसी ने कहा कि बायो बबल का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और अब टीम ने अपनी क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है, इसलिए वे अब बायो सुरक्षित बबल के आसपास ज्यादा आजादी से घूम फिर सकते हैं जिसमें गोल्फ खेलना भी शामिल है। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 2 टेस्टों की सीरीज के लिए ईसीबी के बायो सुरक्षित वातावरण में थी और उसे सोमवार को आईसीसी वातावरण में शिफ्ट किया गया था। इस बीच भारतीय टीम को 24 सदस्यों से कम करते हुए 15 सदस्यों का किया गया है। वहीं शेष खिलाड़ियों और उनके परिवारों को लंदन भेज दिया है। भारतीय टीम से रिलीज किए गए खिलाड़ी लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुन्दर, शार्दुल ठाकुर, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा आवेश खान और अर्जन नागवसवाला है जिन्हें सलाह दी गई है कि वे मैच को स्टैंड्स से देख सकते हैं और फाइनल के दौरान खिलाड़ियों से नहीं जुड़ सकते।

भारत की 15 सदस्यीय टीम इस प्रकार है :

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्या रहाणे , ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन , मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा और उमेश यादव।

पीएसएल में जजाई ने आक्रामक पारी से जीता पेशावर जाल्मी

आबूधाबी, (एजेंसी)। आक्रामक सलामी बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजाई ने पीएसएल में 26 गेंदों पर ही 63 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। जजाई की इस पारी से पेशावर जाल्मी ने कराची किंग्स को छह विकेट से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कराची किंग्स 20 ओवर में नौ विकेट पर केवल 108 रन ही बना पायी। इसके बाद जजाई की पारी से पेशावर जाल्मी ने ये लक्ष्य 11 ओवर में ही हासिल कर लिया। इसी के साथ ही पीएसएल अंकतालिका में पेशावर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। आमिर ने इस मैच में दो ओवर में 31 रन दिए। आमिर के पहले ओवर में कामरान अकमल और जजाई ने 10 रन बनाये। कराची किंग्स की तरफ से तीसरा ओवर डालने आए आमिर पर जजाई ने तीन चौके और एक छक्के की मदद से 21 रन बटोरे। इसके साथ ही वह पीएसएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने के मामले में कामरान अकमल और आसिफ अली के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर पहुंच गए हैं।. जजाई को उनकी तूफानी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। पिछले मैच में 81 रन की पारी खेलने वाले बाबर आजम पहले ही गेंद पर कप्तान वहाब रियाज का शिकार बने। मार्टिन गप्टिल (4), चैडविक वॉल्टन (0) और शरजील खान (25) कुछ खास नहीं कर पाए। कप्तान इमाद वसीम (31 गेंद में 19 रन) और अब्बास अफरीदी (18 गेंद में 27 रन) ने कराची को 100 के पार पहुंचाया। पेशावर के कप्तान वहाब रियाज और अबरार अहमद ने 34 और 14 रन देकर 3-3 विकेट लिए। दो साल बाद मैदान में उतरे समीन गुल ने भी शानदार प्रदर्शन किया।

ओमाहा में पुरुषों के 400 मीटर ओलंपिक तैराकी ट्रायल्स में भाग लेते हुए मिटशेल।

ड्रॉ के साथ ही भारत एशियाई कप क्वालीफायर्स के तीसरे दौर में पहुंचा

दोहा, (एजेंसी)। अफगानिस्तान के साथ यहां मुकाबला ड्रॉ रहने के साथ ही भारतीय फुटबॉल टीम एएफसी एशियाई कप क्वालीफायर्स के तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रही है। इस मैच में अफगान गोलकीपर के एक आत्मघाती गोल से मिली बढ़त को भारतीय टीम बरकरार रखने में विफल रही और एक-एक के ड्रॉ के साथ ही टीम एएफसी एशियाई कप क्वालीफायर्स के तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रही। दोनों टीमें पहले ही विश्व कप 2022 की दौड़ से बाहर हो गई थी। एएफसी एशियाई कप क्वालीफायर्स के तीसरे दौर में पहुंचने के लिए भारत को एक ड्रॉ जबकि अफगानिस्तान को जीत की जरूरत थी।

भारतीय टीम इस ड्रा मुकाबले के बाद ग्रुप ई में तीसरे स्थान पर रही। भारत के नाम आठ मैचों में एक जीत, चार ड्रा और तीन हार से सात अंक रहे जबकि अफगानिस्तान इतने ही मैचों में छह अंक के साथ चौथे स्थान पर है। मैच के 75वें मिनट में अजीजी के हाथ से निकलकर गेंद गोल में चली गयी और भारत को 1-0 की बढ़त मिल गयी। भारतीय टीम हालांकि ये बढ़त ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही और अफगानिस्तान ने होसैन जमानी के गोल से 82वें मिनट में स्कोर 1-1 कर दिया। अफगानिस्तान ने आखिरी क्षणों में आक्रामक खेल दिखाया लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति ने उन्हें और गोल करने का मौका नहीं दिया।

वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित

सिडनी, (एजेंसी)। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए अपनी 20 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। इनमें से 18 खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं, जबकि दो खिलाड़ियों को रिजर्व प्लेयर्स के रूप में टीम में जगह दी गई है। वहीं, सात खिलाड़ियों ने इन दोनों देशों के दौरे पर जाने से इंकार कर दिया है। इन दोनो दौरों से उपकप्तान पैट कमिंस, ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, ओपनर डेविड वार्नर, पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस के अलावा झाय रिचर्डसन और केन रिचर्डसन ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं टीम के कोच जस्टिन लैंगर ने कहा है कि टी20 विश्व कप से पहले इन खिलाड़ियों का टीम से बाहर रहना अच्छे संकेत नहीं है।

इसमें स्टीव स्मिथ ने कोहनी की चोट के कारण दौरे पर नहीं जाने का फैसला किया है, जबकि सीए ने जो सूची जारी की है, उसमें 6 अन्य खिलाड़ियों ने अलग-अलग कारणों से वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के दौरे के लिए अपने को उपलब्ध नहीं बताया है। ऑलराउंडर डैनियल सैम्स, जो भारत में आइपीएल के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस दौरे से अपना नाम वापस लिया है।

वहीं दूसरी ओर मुख्य चयनकर्ता ट्रेवर होन्स ने अपने एक बयान में कहा, हम स्वाभाविक रूप से निराश हैं कि इस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए सभी खिलाड़ी उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि एनएसपी (राष्ट्रीय चयन पैनल) उन लोगों के फैसलों का सम्मान करता है जिन्होंने इस दौरे से बाहर होने का विकल्प लिया है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम इस प्रकार है

आरोन फिंच (कप्तान), एस्टन एगर, वेस एगर, जेसन बेहरनडॉर्फ, एलेक्स कैरी, डैन क्रिस्चियन, जोश हेजलवुड, मोइजेज हेनरिक्स, मिचेल मार्श, बेन मैकडरमोट, रिले मेरेडिथ, जोश फिलिपी, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेप्सन, एस्टन टर्नर, एंड्रयू टाय, मैथ्यू वेड और एडम जैम्पा।

रिजर्व खिलाड़ियों में नाथन एलिस और तनवीर संघा को चुना है।

डब्ल्यूटीसी मुकाबले में अश्विन और जडेजा दोनों को शामिल करें : लक्ष्मण

हैदराबाद। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है कि आर अश्विन और रवींद्र जडेजा दोनों को ही न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए भारतीय टीम में शामिल किया जाना चाहिये। लक्ष्मण के अनुसार अश्विन और जडेजा गेंदबाजी के साथ ही बल्लेबाजी में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऑफ स्पिनर अश्विन और जडेजा ने साल 2014 के अपने दौरे पर इंग्लैंड में एक साथ सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला। अश्विन का इंग्लैंड में गेंद से 32.92 और बल्ले से 25.77 का औसत है जबकि जडेजा का गेंद 55 और बल्ले से 42.37 का औसत रहा है। दोनों क्रिकेटरों ने साल 2014 और 2018 में इंग्लैंड में पिछले 2 दौरों में कम से कम 5 टेस्ट खेले हैं। लक्ष्मण ने कहा, मैं निश्चित रूप से दोनों स्पिनरों को अपनी टीम में रखूंगा क्योंकि जडेजा ने हाल के दिनों में जिस प्रकार दबाव के बीच आक्रामक पारियां खेली हैं उनका जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि जडेजा नंबर 7 पर बल्लेबाज के रूप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बाएं हाथ के होने के नाते यह भारतीय बल्लेबाजी क्रम को बढ़त भी दिलाएंगे। उन्होंने कहा, जहां तक गेंदबाजी का सवाल जडेजा अब एक बहुमुखी गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने एक गेंदबाज के रूप में सुधार किया है, वह टेस्ट के पहले दिन ही बल्लेबाजों को ढेर कर सकते हैं, उन्होंने उस पहलू में सुधार किया है। वहीं लक्ष्मण ने अश्विन की तारीफ करते हुए कहा कि वह सर्वकालिक महानों में से एक हैं। उन्होंने कहा, अश्विन एक शीर्ष श्रेणी के ऑफ स्पिनर हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह टेस्ट क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक हैं। जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में प्रदर्शन किया था वह विदेशों में उनकी क्षमता का एक उदाहरण है।

पिच को लेकर ईसीबी ने मांगी माफी

लंदन। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच टेस्ट मुकाबले के लिए नई पिच की व्यवस्था नहीं कर पाने के लिए माफी मांगी है। ऐसे में दोनों ही टीमों को 37 ओवर पुरानी सतह पर खेलने होंगे। इस स्थल पर पिछले हफ्ते एक टी20 ब्लास्ट मैच की मेजबानी हुई थी। हम सभी निराश हैं, हम जानते हैं कि इंग्लैंड की महिलाएं नई पिच पर खेलने की हकदार थीं और हमें खेद है कि हम ऐसा करने में विफल रहे।

ऑस्ट्रेलियाई टीम में भारत जैसी गहरायी लानी होगी : पेन

मेलबर्न, (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन ने कहा है कि हमें भारत से सीखकर उसके जैसी गहरायी वाली टीम बनानी होगी। पेन ने कहा कि तभी हम अपने प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दे पायेंगे। पेन का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को ऐसे युवाओं की जरूरत है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करके सीनियर खिलाड़ियों का कार्यभार कम कर सकें। उन्होंने कहा, यह जरूरी है कि हम अपनी टीम में ऐसी गहराई पैदा करें, जिससे खिलाड़ियों को समय-समय पर आराम दिया जा सके।

उन्होंने कहा, इस समय भारतीय टीम ऐसा ही कर रही है। उनके पास टेस्ट क्रिकेट के लिए प्रतिभाओं की कमी नहीं है और संतुलन एकदम सही है। हमें भी उनका अनुकरण करना होगा, जिससे अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को आराम दे सकें और अगली बार खेलने पर वे तरोताजा रहें। ऑस्ट्रेलिया को सीमित ओवरों की सीरीज के लिये अभी वेस्टइंडीज का दौरा करना है और उसके बाद उसे बांग्लादेश में सीरीज खेलनी है। अक्टूबर-नवंबर में टी20 विश्व कप भी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को नवंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और आठ दिसंबर से एशेज सीरीज भी खेलनी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अनुभवी खिलाड़ी स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर, पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, झाय रिचर्डसन, केन रिचर्डसन वेस्टइंडीज दौरे से बाहर रह सकते हैं। पेन ने कहा कि इन खिलाड़ियों को आराम की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह एक मसला है मैं नहीं जानता कि कौन दौरे से बाहर रहेगा लेकिन आधुनिक समय में अति व्यस्तता एक बड़ी चुनौती है। वहीं कुछ पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो सही नहीं है। आप उनकी जगह खुद को रखकर देखें जो दौरे से आते हैं और फिर होटल में दो सप्ताह क्वारंटाइन पर रहते हैं। यह काफी थकाऊ होने के साथ ही मानसिक रुप से परेशान करने वाला है।

सचिन ने पुजारा के आलोचकों को आड़े हाथों लिया

मुम्बई, (एजेंसी)। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के आलोचकों को जमकर फटकारा है। आलोचकों का मानना है कि पुजार बेहद धीमी बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए उन्हे टीम में जगह नहीं दी जानी चाहिये। सचिन ने आलोचना को आइना दिखाने हुए कहा कि पुजारा की बल्लेबाजी शैली भारतीय टीम की सफलता का अभिन्न अंग है और ऐसे लोग ही उनकी आलोचना करते हैं जिन्होंने उनके समान उपलब्धियां अर्जित नहीं की हैं। ऑस्ट्रेलिया में अच्छे प्रयास के बाद भी पुजारा को इस बात के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है कि वह तेजी से रन बनाने का जज्बा नहीं दिखाते है। तेंदुलकर ने कहा कि पुजारा को लेकर यह दृष्टिकोण गलत है। तेंदुलकर ने कहा, मुझे लगता है कि पुजारा ने भारत के लिए जो हासिल किया है, उसकी हमें सराहना करनी चाहिए। यह हमेशा स्ट्राइक-रेट के बारे में नहीं होता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको अपनी टीम में फिट होने के लिए अलग तरह की योजना और विभिन्न प्रकार के खिलाड़ियों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, यह आपके हाथों में पांच उंगलियों की तरह है। हर उंगली की एक अलग भूमिका होती है और पुजारा हमारी टीम का अभिन्न अंग हैं।

पुजारा ने भारत के लिए जो किया वह मुझे बहुत पसंद है। उसकी हर पारी को परखने की जगह, उसने भारत के लिए जो किया है हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। साथ ही कहा, जो लोग उसकी तकनीक और रन बनाने की क्षमता पर सवाल उठाते है, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने पुजारा जितना शीर्ष स्तर का क्रिकेट खेला है। तेंदुलकर को लगता है कि टी20 के कारण लोगों का नजरिया बदल गया है, जहां केवल एक ही कौशल की सराहना की जाती है और वह है गेंद को मैदान से बाहर करने का।

सेन डियागो में अमेरिकी ओपन गोल्फ में खेलते हुए बोक्स कोइपका।

कोविड-19 योद्धाओं के लिए पदक जीतना चाहती है महिला हॉकी टीम : रानी

बेंगलुरू। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने कहा है कि उनका लक्ष्य कोविड-19 योद्धाओं के लिए ओलंपिक पदक जीतना रहेगा। रानी ने कहा कि टीम की तैयारियों अच्छी हैं और वह पदक जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। टीम अपने पदक को कोविड जीवनरानी को समर्पित करना चाहती है। रानी ने कहा कि (साइ) केंद्र में ट्रेनिंग कर रहे कोर संभावित खिलाड़ियों का इस हफ्ते चयन ट्रायल होगा जिसके बाद टोक्यो खेलों के लिए टीम का चयन होगा। ओलंपिक में अब 40 दिन से कम का समय बचा है और ऐसे में वह और टीम के उनके साथी प्रत्येक ट्रेनिंग सत्र का फायदा उठाना चाहती हैं रानी ने कहा कि जिन लोगों ने महामारी के दौरान जीवन बचाने के लिए कई बलिदान दिए उनके लिए टोक्यो खेलों में पदक जीतना टीम के लिए शानदार होगा। उन्होंने कहा कि यह ओलिम्पिक अतीत के ओलिम्पिक की तरह नहीं होंगे। हमारे देश को कठिन हालात का सामना करना पड़ा है, हमें अपने डॉक्टरों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों पर गर्व है जिन्होंने जीवन बचाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया है। अब जब हम टोक्यो ओलिम्पिक खेल 2020 में पदक जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे प्रयास और उम्मीद करते हैं कि हमारी जीत डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा सहायकों को समर्पित होगी जिन्होंने भारत में पिछले साल महामारी के फैलने के बाद से बिना थके काम किया है। उनके कारण हम सभी यहां हैं और सुरक्षित हैं। पिछले साल राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान टीम ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके के 1000 से अधिक परिवारों के लिए कोष जुटाने में मदद की थी।